- 19th Year
- Issue: 296
- 08.03.2026 (SUNDAY)
- ROURKELA
- R.N.I. No. ORIHIN/2006/18978
- (Pages-6)
- Price:2.00

दैनिक

कलिंग समाचार

The kalingasamachar

e-paper-www.thekalingasamachar.com

प्रकाशक एवं संपादक : प्रकाश कुमार धल

Published From ODISHA, JHARKHAND & CHHATTISHGARH

राहुल गांधी को अमित शाह की खुली चुनौती, बोले-आप जितना चाहें विरोध करें, हम सीएए से नागरिकता देंगे

नयी दिल्ली ०७/०३ (संवाददाता):केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को घोषणा की कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए 200 शरणार्थियों को नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत नागरिकता प्रदान की गई है। उन्होंने जोर देकर कहा कि हिंदू शरणार्थियों को भारत में उतना ही अधिकार है जितना प्रधानमंत्री को। जन-जन की सरकार- चार साल बेमिसाल कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए लगभग 200 लोगों को नागरिकता दी गई है। जब मैंने सीएए कानून लाया था, तब कांग्रेस, सपा, बसपा, ममता बनर्जी और डीएमके समेत कई लोगों ने इसका विरोध किया था।

अमित शाह ने कहा कि मैं आज फिर से कहना चाहता हूं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों को देश में उतना ही अधिकार है जितना प्रधानमंत्री मोदी को है। उन्होंने आगे कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति ने पहले उन्हें उनके अधिकारों से वंचित रखा था। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को विशेष रूप से चुनौती देते हुए कहा कि सरकार विरोध प्रदर्शनों की परवाह किए बिना नागरिकता प्रदान करने की प्रक्रिया जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि राहुल बाबा, आप चाहे जितना भी विरोध करें, हम ऐसे लोगों को नागरिकता प्रदान करेंगे।

औपनिवेशिक काल से हुए बदलावों पर प्रकाश डालते हुए गृह मंत्री ने भारत की न्याय प्रणाली में आए परिवर्तनों का भी उल्लेख किया और इस बात पर जोर दिया कि भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के पक्ष में पुराने कानूनों को निरस्त कर दिया गया है। उन्होंने घोषणा की कि वर्ष 2028 तक सभी कानूनों का पूर्णत: कार्यान्वयन हो जाएगा। उन्होंने आगे बताया कि धामी प्रशासन के चार वर्ष पूरे होने के साथ ही राज्य में भाजपा के नौ वर्ष के शासन का समय भी समाप्त हो रहा है।

शाह ने उज़राखंड के पहचान संघर्ष पर प्रकाश डालते हुए राज्य की संस्कृति के लिए संघर्ष करने वाले युवाओं की प्रशंसा की और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर राज्य निर्माण आंदोलन के दौरान इन प्रयासों को दबाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि एक समय था जब राज्य अपनी पहचान और अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा था। उज़राखंड की संस्कृति को बचाने के लिए यहां के युवाओं ने लड़ाई लड़ी। उस समय कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने राज्य के युवाओं का दमन किया। तत्कालीन भाजपा मंत्रियों और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उज़राखंड के निर्माण के लिए काम किया।

सीमाओं के साथ संस्कृति को भी बचाना होगा-राजनाथ

हरिद्वार ०७/०३ (संवाददाता): रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को इस बात पर जोर दिया कि देश की संस्कृति और सज़्यता की रक्षा करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि उसकी सीमाओं की सुरक्षा करना, और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को रेखांकित किया। हरिद्वार में सप्तऋषि आश्रम में स्वामी सत्यमित्रानंद की प्रतिमा के अनावरण समारोह को संबोधित करते हुए सिंह ने भारत की सांस्कृतिक पहचान और मूल्यों की रक्षा का आग्रह किया और चेतावनी दी कि कमजोर सांस्कृतिक जड़ें विघटन का कारण बन सकती हैं। आमतौर पर यह माना जाता है कि रक्षा मंत्री की जिज़्मेदारी केवल सीमाओं और सशस्त्र बलों की सुरक्षा तक ही सीमित होती है। हालांकि, मेरा मानना है कि किसी राष्ट्र की सुरक्षा उसकी भौगोलिक सीमाओं से परे तक फैली हुई है। सांस्कृतिक पहचान और सज़्यता की रक्षा करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

शिक्षित महिलाएं ही विकसित राष्ट्र की ताकत है-राष्ट्रपति मुर्मू

नयी दिल्ली ०७/०३ (संवाददाता): अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि शिक्षित और सशक्त महिलाएं एक समृद्ध और प्रगतिशील राष्ट्र में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं। शनिवार को जारी एक संदेश में राष्ट्रपति ने जोर देकर कहा कि महिलाएं हमारे समाज और राष्ट्र की नींव हैं।

राष्ट्रपति ने कहा कि महिलाओं ने शिक्षा, विज्ञान, खेल, कला और रक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा और कड़ी मेहनत का प्रदर्शन किया है। शिक्षित, आत्मनिर्भर और सशक्त महिलाओं के एक समृद्ध और प्रगतिशील राष्ट्र में महत्वपूर्ण योगदान देने का उल्लेख करते हुए मुर्मू ने कहा कि युवा महिलाएं एक नए भारत के सपनों को आकार दे रही हैं, और उन्हें उचित अवसरों, मार्गदर्शन और प्रोत्साहन की आवश्यकता है।

राष्ट्रपति ने कहा, आइए हम सब मिलकर एक ऐसे समाज की दिशा में काम करें जहां महिलाओं को समान अवसर मिलें और वे अपनी क्षमताओं के आधार पर आगे बढ़ सकें और सफलता प्राप्त कर सकें।卐 मुर्मू ने महिला दिवस के सफल आयोजन और सभी महिलाओं के उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं।

यूजीसी प्रोटेस्ट केस में दिल्ली पुलिस को कोर्ट की फटकार, पूछा-10 आरोपियों को क्यों नहीं भेजा नोटिस?

नयी दिल्ली ०७/०३ (संवाददाता): दिल्ली पुलिस ने राउज़ एवेन्यू अदालत से आगे की जांच के लिए समय मांगा है और 2025 में जंतर-मंतर पर यूजीसी विनियम मसौदे के विरोध प्रदर्शन से संबंधित मामले में स्थिति रिपोर्ट दाखिल की है।

2025 में संसद स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई थी और राहुल गांधी, के सी वेणुगोपाल, अखिलेश यादव, ए राजा और कनिमोझी सहित कई नेताओं के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है। अतिरिक्त मुज़्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) अश्वनी पंवार ने सुनवाई की, जिसमें दिल्ली पुलिस ने स्थिति रिपोर्ट दाखिल की और आगे की जांच के लिए समय मांगा।

राउज़ एवेन्यू अदालत ने इससे पहले दिल्ली पुलिस से पूछा था कि प्रस्तावित आरोपियों को जांच में शामिल होने के लिए नोटिस ज़्यों नहीं जारी किए गए और 10 आरोपियों को नोटिस जारी किए बिना पुलिस रिपोर्ट ज़्यों दर्ज की गई।

19 फरवरी को पिछली सुनवाई में सहायक न्यायाधीश पारस दलाल ने उल्लेख किया था कि आरोपपत्र में 11 व्यक्तियों को आरोपी बनाया गया है। पुलिस रिपोर्ट से पता चलता है कि एक आरोपी, सीवीएमपी एझिलारासन को 7 अप्रैल, 2025 को ईमेल के माध्यम से बीएनएसएस की धारा 35(3) के तहत जांच में शामिल होने के लिए नोटिस जारी किया गया था, अदालत ने यह बात नोट की थी। अदालत ने आगे नोट किया कि पुलिस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि आरोपी जांच में शामिल नहीं हुआ। जांच अधिकारी (आईओ) द्वारा आरोपी सीवीएमपी एझिलारासन को इस मामले की जांच में शामिल करने के लिए कोई और कदम नहीं उठाया गया। अन्य 10 आरोपियों के संबंध में, जांच अधिकारी द्वारा इस मामले की जांच में शामिल होने के लिए कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था।

अदालत ने पाया कि जांच अधिकारी ने सत्येंद्र कुमार अंतिल मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का पालन नहीं किया और दिल्ली पुलिस के 2020 के स्थायी आदेश का उल्लंघन किया।

रुसी तेल यूएस की छूट? केन्द्र का दो टूक जवाब-हमें किसी की अनुमति नहीं चाहिए

नयी दिल्ली ०७/०३ (संवाददाता): केंद्र सरकार ने शनिवार को कहा कि ईरान-अमेरिका-इजराइल युद्ध के बीच होर्मुज जलडमरूमध्य में तनाव जारी रहने के बावजूद, भारत सबसे प्रतिस्पर्धी कीमतों की पेशकश करने वाले स्रोत से कच्चे तेल की खरीद जारी रखेगा। सरकार ने एक बयान में कहा कि व्यवधानों के बावजूद भारत की ऊर्जा आपूर्ति सुरक्षित बनी हुई है। केंद्र सरकार ने एक बयान में कहा कि होर्मुज मार्ग पर बढ़ते तनाव के बावजूद, भारत की ऊर्जा आपूर्ति सुरक्षित और स्थिर बनी हुई है। भारत ने कच्चे तेल के स्रोतों को 27 से बढ़ाकर 40 देशों तक कर लिया है, जिससे कई वैकल्पिक आपूर्ति मार्ग सुनिश्चित हो गए हैं। राष्ट्रीय हित में, भारत तेल वहीं से खरीदता है जहां सबसे प्रतिस्पर्धी और किफायती दरें उपलज़्ध हों।

भारत ने शनिवार को यह भी पुष्टि की कि वह मध्य पूर्व में चल रहे युद्ध के कारण अमेरिका द्वारा दी गई अस्थायी छूट का हवाला देते हुए रूसी तेल का आयात जारी रखेगा। केंद्र ने कहा कि नई दिल्ली को इस तरह की खरीद के लिए किसी भी देश से अनुमति की आवश्यकता नहीं है। केंद्र ने कहा कि भारत ने रूसी तेल खरीदने के लिए कभी भी किसी देश की अनुमति पर निर्भर नहीं किया है। भारत फरवरी 2026 में भी रूसी तेल का आयात जारी रखेगा और रूस अभी भी भारत का सबसे बड़ा कच्चे तेल का आपूर्तिकर्ता है। रूस-यूक्रेन युद्ध के तीन वर्षों के दौरान, भारत ने अमेरिका और यूरोपीय संघ की आपज़ियों के बावजूद रूसी तेल खरीदना जारी रखा। रियायती कीमतों और रिफाइनरी की मांग के कारण 2022 के बाद आयात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।केंद्र सरकार के अनुसार, भारत के पास कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों का भंडार है, जो भंडार और आपूर्ति श्रृंखला दोनों में 25 करोड़ बैरल से अधिक है। यह भंडार 7 से 8 सप्ताह की खपत के बराबर है। भारत की कुल शोधन क्षमता 25 करोड़ मीट्रिक टन प्रति वर्ष है, जो वर्तमान घरेलू मांग से अधिक है।

नीतीश के रास जाने पर अखिलेश का कटाक्ष, कहा-हम तो पीएम पद से चाहते थे विदाई

नयी दिल्ली ०७/०३ (संवाददाता): समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा की आलोचना करते हुए कहा कि वे चाहते थे कि जेडीयू प्रमुख प्रधानमंत्री पद से सेवानिवृज़ हों। यह आलोचना बिहार के मौजूदा मुज़्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 2026 के राज्यसभा चुनावों के लिए नामांकन दाखिल करने के बाद की गई। शुक्रवार को पत्रकारों से बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि राजनीति की समझ रखने वाला जानता था कि भाजपा ज़्या कदम उठाएगी। हम चाहते थे कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद से सेवानिवृज़ हों, लेकिन अब वे राज्यसभा सदस्य के रूप में सेवानिवृज़ होंगे।

2024 के आम चुनावों से पहले एनडीए में फिर से शामिल होने से पहले, नीतीश कुमार इंडिया ज़्लॉक के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और उनके समर्थक उन्हें प्रधानमंत्री पद का उज़्मीदवार मानते थे। इस बीच, बिहार के मंत्री श्रवण कुमार ने शनिवार को कहा कि जनता दल (यूनाइटेड) के कार्यकर्ता नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले से नाराज हैं, लेकिन उन्होंने उनका साथ देने और समर्थन करने का संकल्प लिया है। एएनआई से बात करते हुए श्रवण कुमार ने कहा कि नीतीश कुमार ने शुक्रवार को एक बैठक में पार्टी नेताओं को अपने फैसले के बारे में स्पष्ट किया।

बिहार के मंत्री ने कहा, कल की बैठक में मुज़्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी मामलों को स्पष्ट कर दिया। राज्यसभा में जाने का यह उनका राजनीतिक निर्णय है।

होली पर हुए छोटे से विवाद में मुस्लिमों ने तरुण को पीट-पीट कर मार डाला

नयी दिल्ली ०७/०३ (संवाददाता): नई दिल्ली के उज़म नगर इलाके में होली के दिन हुआ एक मामूली-सा विवाद हिंसक झड़प में बदल गया और 26 वर्षीय युवक तरुण बुटोलिया की जान चली गई। चार मार्च को हुई इस घटना ने पूरे इलाके को तनाव और भय के माहौल में डाल दिया है। हम आपको बता दें कि एक बच्चे की खेल खेल में हुई छोटी-सी गलती ने कुछ ही देर में ऐसा रूप ले लिया कि एक परिवार की खुशियां उजड़ गईं और पूरा मोहल्ला स्तज़्ध रह गया।

जानकारी के अनुसार विवाद की शुरुआत उस समय हुई जब तरुण के परिवार की 11 वर्षीय बच्ची अपने घर की छत पर होली खेल रही थी। इसी दौरान उसने पानी से भरा गुज़्बारा फेंका जो पास के घर की एक महिला पर गिर गया। यह महिला दूसरे धर्म की है। बताया जा रहा है कि तरुण के परिवार ने तुरंत माफी भी मांग ली थी, लेकिन बात यहीं समाप्त नहीं हुई। आरोप है कि महिला ने अपने रिश्तेदारों को फोन कर बुला लिया जिससे तनाव बढ़ गया।करीब एक घंटे बाद स्थिति और गंभीर हो गई। उस समय तरुण बुटोलिया एक होली पार्टी में गया हुआ था। तभी उसे फोन कर बताया गया कि उसके माता पिता पर हमला किया जा रहा है। यह सुनकर वह तुरंत मोटरसाइकिल से घर की ओर लौट पड़ा। उसकी मां सुनीता बुटोलिया ने बताया कि फोन पर कहा गया था कि परिवार के लोगों को पीटा जा रहा है। मां ने बताया कि उनका बेटा उन्हें बचाने के लिए आया, लेकिन हमलावर पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे।

जब तरुण अपने घर के पास संकरी गली में पहुंचा तो वहां माहौल बेहद तनावपूर्ण था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार इलाके के कुछ लोगों ने हमलावरों से झगड़ा रोकने की अपील भी की, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। देखते ही देखते सात से आठ लोगों ने तरुण को घेर लिया और उस पर डंडों, बल्लों, ईंटों और पत्थरों से हमला कर दिया।

परिवार के अनुसार तरुण जिम जाता था और शारीरिक रूप से मजबूत था। उसने खुद को बचाने की कोशिश भी की, लेकिन एक साथ कई लोगों के हमले के सामने वह ज्यादा देर टिक नहीं सका। बताया जाता है कि हमलावरों ने उसे बुरी तरह पीटा। यहां तक कि जब वह खून से लथपथ होकर गिर पड़ा और बेहोश हो गया तब भी हमला जारी रहा। आरोप है कि उसके बाद भी उसे लगातार मारा गया और उस पर धारदार वार किये गये। तरुण की मां ने घटना को बेहद भयावह बताते हुए कहा कि भीड़ लगातार घर पर पत्थर भी फेंक रही थी और लोहे की रेलिंग को नुकसान पहुंचाया गया। परिवार के लोग डर के कारण घर के अंदर बंद हो गये थे। उनका कहना है कि तरुण का इस विवाद से कोई लेना देना नहीं था, वह केवल अपने माता पिता की मदद करने के लिए घर लौटा था।

हम आपको बता दें कि तरुण के पिता ममराज बुटोलिया सफेदी का काम करते हैं। उनकी बेटी रेखा के अनुसार तरुण ने बीसीए की पढ़ाई की थी और वह डिजिटल आर्किटेक्चर और डिजाइन का ऑनलाइन कोर्स कर रहा था। वह मकानों के नज़्शे बनाता था और भविष्य में इस क्षेत्र में कॅरियर बनाना चाहता था। परिवार का कहना है कि उसके बड़े सपने थे जो अब अधूरे रह गये।घटना के बाद इलाके में तनाव और बढ़ गया। चार मार्च की घटना के दो दिन बाद आरोपियों के रिश्तेदारों की बताई जा रही एक कार और एक मोटरसाइकिल को आग के हवाले कर दिया गया। इसके बाद स्थिति को देखते हुए इलाके में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। सीआरपीएफ के जवान तैनात किये गये हैं, जगह जगह बैरिकेड लगाये गये हैं और ड्रोन से निगरानी की जा रही है।

पुलिस के अनुसार अब तक एक नाबालिग सहित आठ लोगों को गिरज़्तार किया जा चुका है। जांच के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है और गवाहों के बयान दर्ज किये जा रहे हैं। हालांकि तरुण का परिवार इस मामले की जांच केंद्रीय एजेंसी से कराने की मांग कर रहा है। उनका कहना है कि कई हमलावर अब भी खुले घूम रहे हैं।

हम आपको बता दें कि इस घटना के विरोध में स्थानीय लोगों और परिवार के सदस्यों ने सड़कों पर प्रदर्शन भी किया। उन्होंने रास्ता जाम कर नारेबाजी की और न्याय की मांग उठाई। कई सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ता भी इन प्रदर्शनों में शामिल हुए जिससे इलाके का माहौल और संवेदनशील हो गया।

पीएम मोदी देंगे दिल्ली मेट्रो को बड़ी सौगात, दो नए कॉरिडोर का उद्घाटन

नयी दिल्ली ०७/०३ (संवाददाता): दिल्ली की मुज़्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को कहा कि दिल्ली मेट्रो नेटवर्क का निरंतर विस्तार राष्ट्रीय राजधानी में कनेज़्टिविटी में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा और स्वच्छ सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देगा। मुज़्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 मार्च को दिल्ली में दो नए मेट्रो कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे और तीन अतिरिक्त कॉरिडोर की आधारशिला रखेंगे। गुप्ता ने कहा कि ये परियोजनाएं राजधानी में तेज, सुगम और पर्यावरण के अनुकूल सार्वजनिक परिवहन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होंगी, साथ ही सड़कों पर निजी वाहनों का दबाव कम करेंगी और प्रदूषण नियंत्रण में मदद करेंगी। मुज़्यमंत्री के अनुसार, प्रधानमंत्री दो मेट्रो कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे - पिंक लाइन का मजलिस पार्क-मौजपुर-बाबरपुर खंड और मैजेंटा लाइन का दीपाली चौक-मजलिस पार्क कॉरिडोर मैजेंटा लाइन का विस्तार है, जिससे लाइन की कुल लंबाई लगभग 49 किलोमीटर तक बढ़ जाएगी। इस विस्तार से कई आवासीय और व्यावसायिक क्षेत्र मेट्रो नेटवर्क से और अधिक जुड़ जाएंगे। मुज़्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नेटवर्क के चरण-ड्ढ के तहत तीन नए मेट्रो कॉरिडोर की आधारशिला भी रखेंगे। गुप्ता ने कहा कि इन परियोजनाओं से न केवल दिल्ली बल्कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के शहरों के यात्रियों को भी लाभ होगा।

पिंक लाइन का मजलिस पार्क-मौजपुर-बाबरपुर खंड के खुलने के साथ, पिंक लाइन की कुल लंबाई लगभग 71.56 किलोमीटर हो जाएगी, जिससे दिल्ली देश की पहली पूर्णत: चालू रिंग मेट्रो बन जाएगी। इस कॉरिडोर से उज़र-पूर्वी और उज़र-पश्चिमी दिल्ली के बीच कनेज़्टिविटी में सुधार होने और शहर के कई हिस्सों में यात्रा का समय कम होने की उज़्मीद है। गुप्ता ने आगे कहा कि दीपाली

विविध समाचार

यूएस डील से तबाह होंगे किसान? राहुल गांधी ने पीएम मोदी को घेरा, कहा-ये देश को बेचना चाहते हैं

नयी दिल्ली ०७/०३ (संवाददाता): कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अमेरिका के साथ व्यापार समझौता करके देशद्रोह करने का आरोप लगाया। उनका दावा है कि इस समझौते से भारत के किसानों और छोटे व्यवसायों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। गांधी ने ये टिप्पणियां केरल विधानसभा में विपक्ष के नेता वी.डी. सतीशान के नेतृत्व में राज्यव्यापी पुथुयुग यात्रा के समापन समारोह का उद्घाटन करते हुए कीं। गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश को निराश किया है। उन्होंने देश के साथ विश्वासघात किया है। मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री ने अमेरिका के साथ समझौता करके देश के साथ विश्वासघात किया है। राहुल ने आरोप लगाया कि आम नागरिक,

विशेषकर किसान और छोटे व्यवसायी, अंततः इस समझौते का बोझ उठाएंगे। उन्होंने कहा कि उनसे पहले किसी भी प्रधानमंत्री ने भारतीय कृषि को अमेरिकी कृषि के लिए नहीं खोला। राहुल ने कहा कि बड़ी और मशीनीकृत अमेरिकी कृषि कंपनियों के भारतीय बाजार में प्रवेश से छोटे किसानों पर भारी दबाव पड़ेगा और कृषि क्षेत्र में भारी तबाही मच सकती है। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि देश का ऊर्जा क्षेत्र प्रभावित हुआ है और दावा किया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने समझौते के माध्यम से भारतीय डेटा प्राप्त किया है। कांग्रेस नेता ने यह भी आरोप लगाया कि मोदी ट्रंप के इशारों पर चलते हैं और कहा कि केरल के मुख्यमंत्री भी इसी तरह मोदी के इशारों पर चलते हैं।

गांधी ने कहा कि एपस्टीन की साढ़े तीन मिलियन फाइलें अभी तक सामने नहीं आई हैं। भारत के प्रधानमंत्री इस बात से भयभीत हैं कि अमेरिका उन फाइलों को जारी कर देगा। प्रधानमंत्री के करीबी अनिल अंबानी का नाम उन फाइलों में है। हरदीप पुरी का नाम भी उन फाइलों में है। हमें पूरा विश्वास है कि उन फाइलों में और भी कई नाम हैं। दूसरी ओर, अमेरिका ने अडानी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया है। प्रधानमंत्री मोदी इस बात से भयभीत हैं कि भाजपा और उनके विज़ीय मामलों का खुलासा भारत की जनता के सामने हो जाएगा। इसीलिए प्रधानमंत्री घबरा गए और उन्होंने अमेरिका-भारत समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। अगर आप यूट्यूब पर खोजेंगे तो पाएंगे कि राष्ट्रपति ट्रंप खुलेआम भारत के प्रधानमंत्री को धमकी दे रहे हैं। वे खुलेआम कहते हैं कि वे प्रधानमंत्री मोदी का करियर बर्बाद कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति ट्रंप के इशारों पर चल रहे हैं।लोकसभा विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि मेरे दोस्तों, वाम मोर्चे के कार्यकर्ताओं, एक सवाल। आप खुद को कज़्युनिस्ट सरकार कहते हैं। कृपया मुझे बताएं कि आज केरल में आपकी सरकार में कज़्युनिस्ट ज़्या है? यह केरल की अब तक की सबसे कॉरपोरेटवादी सरकार है... दरअसल, मेरे पास उनके लिए एक सुझाव है। आपका नाम कज़्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है। इसे बदलकर कॉरपोरेटिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कर दीजिए। कम से कम अपने कहे अनुसार तो खड़े रहिए।

सुप्रीम कोर्ट से प्रशांत किशोर की जन सूराज को फटकार, हार के बाद लोकप्रियता के लिए कोर्ट न आएं

नयी दिल्ली ०७/०३ (संवाददाता): शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने जन सूरज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि चुनाव हारने के बाद उज़्मीदवारों को अदालतों का रुख नहीं करना चाहिए। बेंच ने टिप्पणी की कि मतदाताओं द्वारा नकारे गए उज़्मीदवारों को लोकप्रियता हासिल करने के लिए न्यायपालिका का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। भारत के मुज़्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की बेंच ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से संबंधित किशोर की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये तीखी टिप्पणियां कीं।

किशोर ने सुप्रीम कोर्ट में आरोप लगाया था कि महिला रोजगार योजना की धनराशि मतदान से ठीक पहले लाभार्थियों के बैंक खातों में स्थानांतरित की गई थी, जिससे उनके अनुसार चुनाव परिणाम प्रभावित हुए थे। हालांकि, चुनाव आयोग ने उनकी याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद किशोर ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। पार्टी द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली तत्कालीन बिहार सरकार ने चुनाव तिथियां तय होने के बाद 10,000 रुपये के प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की घोषणा से पहले जानबूझकर मुज़्यमंत्री महिला रोजगार योजना में अतिरिक्त लाभार्थियों को जोड़ा।

पार्टी का दावा है कि यह स्वयं में मतदाताओं को अनुचित रूप से लुभाने और प्रभावित करने के लिए अपनाई गई भ्रष्ट कार्यप्रणाली का स्पष्ट प्रमाण है, ताकि वे सज़ाधारी सरकार के पक्ष में मतदान करें। पार्टी ने आरोप लगाया है कि इस योजना के लिए कानून पारित करने के बजाय बिहार के आकस्मिक निधि का उपयोग करना संविधान के अनुच्छेद 267 का उल्लंघन है। जन सूरज की याचिका में कहा गया है कि यह अत्यंत विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि संदर्भित योजना को चुनाव की पूर्व संध्या पर मंत्रिमंडल के निर्णय द्वारा बिना किसी विधायी स्वीकृति के लागू किया गया था और याचिकाकर्ता की जानकारी के अनुसार, इस योजना का बजट बिहार राज्य की आकस्मिक निधि से लिया गया था। अतः, उक्त योजना नियमित बजटीय आवंटन का हिस्सा नहीं थी, बल्कि राज्य की आकस्मिक निधि से ली गई थी, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 267 का उल्लंघन है। विधानसभा चुनावों में, सज़ारूढ़ एनडीए को 243 सदस्यीय सदन में तीन-चौथाई बहुमत के साथ 202 सीटें मिलीं। यह दूसरी बार है जब एनडीए ने विधानसभा चुनावों में 200 का आंकड़ा पार किया है। 2010 के चुनावों में, इसने 206 सीटें जीती थीं।

एलपीजी मूल्यवृद्धि पर पवन खेरा का हमला, कहा-हरदीप पुरी की बातों पर विश्वास न करें

नयी दिल्ली ०७/०३ (संवाददाता): कांग्रेस के मीडिया एवं प्रचार विभाग के अध्यक्ष पवन खेड़ा ने शनिवार को एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी की कड़ी आलोचना की। घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की कीमतें शनिवार, 7 मार्च से बढ़ा दी गई हैं। देश भर में 14.2 किलोग्राम के घरेलू खाना पकाने वाले गैस सिलेंडर की कीमत में 60 रुपये की वृद्धि हुई है, और 19 किलोग्राम के व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत में भी 115 रुपये की वृद्धि हुई है।

पवन खेड़ा ने फेसबुक पर लिखा कि कल, हरदीप सिंह पुरी ने कहा था- %हमारी प्राथमिकता अपने नागरिकों के लिए किफायती और टिकाऊ ईंधन की उपलज़्धता सुनिश्चित करना है, और हम इसे आसानी से कर रहे हैं।% आज, घरेलू एलपीजी की कीमतों में 60 रुपये और व्यावसायिक सिलेंडरों की कीमतों में 115 रुपये की वृद्धि हुई है। हरदीप सिंह पुरी की किसी भी बात पर विश्वास न करें। खेड़ा की ये टिप्पणी केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी के उस बयान के जवाब में आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत में ऊर्जा की कोई कमी नहीं है और पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के बीच ऊर्जा उपभोक्ताओं को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।केंद्रीय मंत्री ने शुक्रवार को ङ्क पर पोस्ट किया कि हमारी प्राथमिकता अपने नागरिकों के लिए किफायती और टिकाऊ ईंधन की

उपलज़्धता सुनिश्चित करना है, और हम इसे बखूबी कर रहे हैं। भारत में ऊर्जा की कोई कमी नहीं है, और हमारे ऊर्जा उपभोक्ताओं को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इस बीच, सूत्रों के अनुसार, दिल्ली में 14.2 किलोग्राम के घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 853 रुपये से बढ़कर 913 रुपये हो गई है। मुंबई में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की नई दर 852.50 रुपये से बढ़कर 912.50 रुपये हो गई है। कोलकाता में कीमत 879 रुपये से बढ़कर 0.30 रुपये हो गई है, जबकि चेन्नई में यह 868.50 रुपये से बढ़कर 928.50 रुपये हो गई है। संशोधित दरें आज से तुरंत प्रभाव से लागू हो जाएंगी।

यह बढ़ोतरी व्यावसायिक उपयोग वाले एलपीजी सिलेंडरों पर भी लागू होती है। दिल्ली में 19 किलोग्राम के व्यावसायिक सिलेंडर की कीमत 1768.50 रुपये से बढ़कर 1883 रुपये हो गई है। मुंबई में यह कीमत 1720.50 रुपये से बढ़कर 1835 रुपये हो गई है। इसी तरह, कोलकाता में यह कीमत 1875.50 रुपये से बढ़कर 1990 रुपये हो गई है, जबकि चेन्नई में यह 1929 रुपये से बढ़कर 2043.50 रुपये हो गई है। इससे पहले, घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत अप्रैल 2025 से अपरिवर्तित थी, जब दिल्ली में गैर-सब्सिडी वाली दर 853 रुपये थी। नवीनतम संशोधन घरेलू उपभोक्ताओं के साथ-साथ उन व्यावसायिक उपयोगकर्ताओं के लिए भी एक महत्वपूर्ण वृद्धि है जो दैनिक कार्यों के लिए एलपीजी पर निर्भर हैं।

गढ़चिरौली मुठभेड़! 24 घंटे से जारी जंग में एक नज़्सली ढेर, सी-60 कमांडो घायल

गढ़चिरौली ०७/०३ (संवाददाता): महाराष्ट्र के घने और दुर्गम जंगलों में देश की सुरक्षा के लिए तैनात सी-60 कमांडो और सुरक्षा बलों ने एक बार फिर अपने अदज़्य साहस और बेजोड़ रणनीति का लोहा मनवाया है। अपनी जान हथेली पर रखकर नज़्सलियों के गढ़ में घुसने वाले इन जांबाज जवानों ने न केवल माओवादियों की साज़िशों को नाकाम किया, बल्कि भीषण गोलीबारी के बीच नज़्सलियों के सुरक्षित ठिकानों को भी नेस्तनाबूद कर दिया। जवानों के इस अटूट हौसले का ही परिणाम है कि भारी चुनौतियों और विपरीत परिस्थितियों के बावजूद नज़्सलियों को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा।महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में पिछले 24 घंटे से जारी मुठभेड़ में एक नज़्सली मारा गया, जबकि एक सी-60 कमांडो घायल हो गया। एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि मंगलवार शाम को प्रतिबंधित भारतीय कज़्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) की कंपनी नंबर 10 के उग्रवादियों की मौजूदगी की खुफिया जानकारी मिलने के बाद भामराग के एसडीपीओ के नेतृत्व में 14 सी-60 यूनिटों के साथगढ़चिरौली-नारायणपुर सीमा पर फोडेवाड़ा गांव के पास यह अभियान शुरू किया गया।परिणामस्वरूप दो नज़्सली शिविरों का भंडाफोड़ हुआ। इस दौरान नज़्सलियों का सामान बरामद हुआ, हालांकि दुर्गम इलाके और घने जंगल के कारण नज़्सलियों का पता नहीं लगाया जा सका। बृहस्पतिवार की सुबह मौजूदा घेराबंदी के तहत अतिरिक्त चार सी-60 यूनिट और सीआरपीएफ की ज़्यूएटी की एक यूनिट को तैनात किया गया।'

नीतीश कब तक देंगे इस्तीफा, नए सीएम का कब होगा शपथ? सूत्रों ने दी बड़ी जानकारी

पटना ०७/०३ (संवाददाता): बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है ज़्योंकि मुज़्यमंत्री नीतीश कुमार राज्य नेतृत्व छोड़कर राष्ट्रीय राजनीति में कदम रखने की तैयारी कर रहे हैं।

लगभग दो दशकों तक बिहार की राजनीति पर अपना दबदबा बनाए रखने वाले इस दिग्गज नेता के राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल करने की उज़्मीद है, जिससे इस बात को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं कि राज्य सरकार की अगली बागडोर कौन संभालेगा। वहीं, सवाल यह भी है कि नया सीएम कब तक मिलेगा।

मुज़्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा में जाने के फैसले के बाद बिहार के राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव की आशंका है, लेकिन सूत्रों के अनुसार, उनके स्थान पर अगले मुज़्यमंत्री के पद पर तत्काल कोई निर्णय नहीं लिया गया है। जनता दल (यूनाइटेड) के शीर्ष सूत्रों ने बताया कि मुज़्यमंत्री का पद 10 अप्रैल के बाद ही खाली होगा और अगले महीने से

पहले उज़राधिकारी के नाम की घोषणा होने की संभावना नहीं है। कुमार के राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण करने की संभावना उसी तारीख के बाद है, जिससे राज्य में नेतृत्व परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त होगा।

सूत्रों ने यह भी संकेत दिया है कि संसद में जाने के बाद भी कुमार पटना को अपना राजनीतिक आधार बनाए रखेंगे और केवल संसद सत्रों के दौरान ही नई दिल्ली की यात्रा करेंगे।

फिलहाल, गठबंधन में कुमार के केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने को लेकर कोई चर्चा नहीं चल रही है। अंदरूनी सूत्रों के अनुसार, कुमार के बिगड़ते स्वास्थ्य को लेकर चिंताओं के चलते उन्हें राज्यसभा भेजने का निर्णय कुछ समय से विचाराधीन था। इन चिंताओं के बावजूद, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) ने शुरू में कुमार को मुज़्यमंत्री बनाए रखने का फैसला किया था ज़्योंकि हालिया चुनाव अभियान उनके नाम पर लड़ा गया था और जनादेश उनके नेतृत्व से जुड़े शासन मॉडल के वादे पर हासिल किया गया था। हालांकि, सूत्रों के अनुसार, पिछले कुछ महीनों में उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया है, जिसके चलते नेतृत्व में बदलाव को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं।

किसानों का 2 लाख का कर्ज माफ, लाडली बहिन योजना भी रहेगी जारी

मुंबई ०७/०३ (संवाददाता): मुज़्यमंत्री और विज़ मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 6 मार्च को विधानसभा में महाराष्ट्र राज्य का बजट पेश किया।

अपने भाषण में उन्होंने मुंबई महानगर क्षेत्र को एक प्रमुख आर्थिक और अवसंरचना केंद्र में बदलने के उद्देश्य से एक विस्तृत विकास योजना प्रस्तुत की। सरकार की योजना अवसंरचना, रसद, आवास, मेट्रो कनेज़्टिविटी और हाई-स्पीड रेल परियोजनाओं को मजबूत करने पर केंद्रित है, जो मुंबई और आसपास के महानगर क्षेत्र के विकास के लिए एक दीर्घकालिक रणनीति का संकेत देती है।

इस बजट के माध्यम से, फडणवीस ने महाराष्ट्र में शहरीकरण के भविष्य को दिशा देने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। सरकार का मानना है कि आने वाले वर्षों में राज्य की लगभग 70त्न आबादी शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन कर सकती है। इस प्रवृज़ि को ध्यान में रखते हुए, प्रशासन ने शहरी बुनियादी ढांचे का व्यापक विस्तार करने के साथ-साथ शहरों में नागरिक सेवाओं के प्रबंधन में सुधार के लिए बड़े पैमाने पर डिजिटल प्रणालियाँ लागू करने का निर्णय लिया है।

गरीब महिलाओं के लिए चलाई जा रही 'लाडकी बहिन' योजना को जारी रखने और इसके लिए पर्याप्त बजटीय प्रावधान करने की भी बात कही गई। मुज़्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य विधानसभा में अगले विज़ वर्ष के लिए 7,69,467 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र वर्ष 2047 तक पांच लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनेगा। विज़ विभाग का भी प्रभार संभाल रहे फडणवीस ने 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर शेतकरी कर्जमाफी योजना' के तहत 30 सितंबर, 2025 तक बकाया दो लाख रुपये तक के फसली ऋण को माफ करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि जो किसान अपने कर्ज की अदायगी नियमित रूप से करते रहे हैं, उन्हें राज्य सरकार की तरफ से 50,000 रुपये का प्रोत्साहन दिया जाएगा।

मुज़्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2024 में शुरू की गई 'मुज़्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना' आगे भी जारी रहेगी। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को प्रति माह 1,500 रुपये दिए जाते हैं और इसके लिए पर्याप्त धन उपलज़्ध कराया जाएगा। इसके साथ ही फडणवीस ने कहा कि राज्य के 1,000 से अधिक आबादी वाले सभी गांवों को कंक्रीट से बनी सड़कों के जरिये जोड़ा जाएगा। उन्होंने महाराष्ट्र को देश की विज़ीय ताकत बताते हुए कहा कि वर्ष 2047 तक राज्य की अर्थव्यवस्था को पांच लाख करोड़ डॉलर के स्तर तक ले जाने का लक्ष्य है। बजट दस्तावेज के मुताबिक, विज़ वर्ष 2026-27 में राज्य की राजस्व प्राप्तियां 6,16,099 करोड़ रुपये और राजस्व व्यय 6,56,651 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। इस तरह अगले विज़ वर्ष में राजस्व घाटा 40,552 करोड़ रुपये रह सकता है।

कलिंग समाचार
THE KALINGA SAMACHAR
(A Hindi Daily News Paper)
PUBLISHED FROM ODISHA, JHARKHAND & CHATTISHGARH
FOR NEWS AND ADVERTISEMENT CONTACT
AT: QRS. NO. B/204, SECTOR-16
ROURKELA, PH. 0661-2646999
PRAKASH KUMAR DHAL (EDITOR)
E-mail: thekalingasamachar@gmail.com

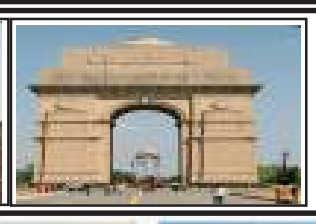

विविध समाचार

फोटोग्राफी में इंट्रेस्टेड छात्रों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराता है निकॉन स्कॉलरशिप प्रोग्राम

निकॉन स्कॉलरशिप प्रोग्राम फोटोग्राफी संबंधित कोर्स करने के शौकीन छात्रों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराती है। यह स्कॉलरशिप प्रोग्राम उन छात्रों के लिए है, जो 12वीं कर चुके है।

निकॉन स्कॉलरशिप प्रोग्राम फोटोग्राफी संबंधित कोर्स करने के शौकीन छात्रों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराती है। यह स्कॉलरशिप प्रोग्राम उन छात्रों के लिए है, जो 12वीं कर चुके हैं और 3 महीने या उससे अधिक की अवधि के लिए फोटोग्राफी संबंधित कोर्स में एडमिशन लिया है। यह स्कॉलरशिप निकॉन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से शुरू की गई एक पहल है। आपको बता दें कि निकॉन कंपनी इंडिया इमेजिंग और ऑप्टिक्स के मैदान में दुनिया की दिग्गज कंपनी है। निकॉन स्कॉलरशिप का उद्देश्य सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिस्से के तौर पर निकॉन इंडिया कॉर्पोरेट स्कॉलरशिप ऑफर कर रही है। बीते कुछ सालों से शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए निकॉन कंपनी कई गतिविधियों का भी आयोजन कर रही है। निकॉन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की ओर से जो भी छात्र अच्छी फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी करते हैं। उनको कंपनी की तरफ से 1 लाख तक की स्कॉलरशिप दी जाती है। ऐसे में अगर आप भी फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी के शौकीन है, तो आप भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

पात्रता

- बता दें कि 3 महीने या उससे ज्यादा की अवधि वाले फोटोग्राफी संबंधित कोर्स करने वाले छात्र इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
- स्टूडेंट्स की 12वीं पास होना जरूरी है।
- छात्र की सालाना पारिवारिक आय 6 लाख रुपए से कम होनी चाहिए।
- यह योजना सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए है।

डॉक्यूमेंट्स

- फोटो पहचान प्रमाण
- आय प्रमाण
- प्रवेश प्रमाण पत्र
- आवेदक का पासपोर्ट साइज का फोटो
- छात्रवृत्ति आवेदक का बैंक अकाउंट का विवरण
- पिछली कक्षा की मार्कशीट या ग्रेड कार्ड
- वर्तमान शैक्षणिक वर्ष की शुल्क रसीद
- विकलांगता और जाति प्रमाण पत्र

ऐसे करें आवेदन

निकॉन स्कॉलरशिप प्रोग्राम का लाभ लेने के लिए सबसे पहले ईमेल/फेसबुक/जीमेल अकाउंट से लॉगिन करें। फिर निकॉन स्कॉलरशिप प्रोग्राम के डिटेल पेज पर जाएं। इसके बाद ऑनलाइन एप्लिकेशन फॉर्म में मांगी गई सभी जरूरी डिटेल्स भर दें। वहीं जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दें। एप्लिकेशन फॉर्म चेक करने के बाद सबमिट पर क्लिक कर दें। इस तरह से आपका फॉर्म भर जाएगा।

डिजिटल स्किल सीखकर डिजिटल सेक्टर में बना सकते हैं शानदार कॅरिअर

मौजूदा साल में देश में करीब 5 करोड़ से भी अधिक लोग बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। जहां देश के तमाम बेरोजगार युवाओं और छात्रों में स्किल्स की कमी देखी गई। ऐसे में देश के युवा डिजिटल स्किल सीखकर डिजिटल सेक्टर में शानदार कॅरिअर बना सकते हैं।

मौजूदा साल में देश में करीब 5 करोड़ से भी अधिक लोग बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। एक आंकड़े के मुताबिक BA, B.Sc. B.Com छात्र या डिग्री कर चुके तकरीबन 19 फीसदी युवा भी इस समस्या से परेशान हैं। वहीं 10वीं-12वीं छात्रों की बेरोजगारी का प्रतिशत 10.3 फीसदी के आसपास है। एक रिपोर्ट की मानें तो भारत में बेरोजगारी दर 7 फीसद के आसपास बनी हुई है। अगर ग्रामीण भारत और शहरी भारत में बेरोजगारी दर को बांटा जाए, तो ग्रामीण भारत की तुलना में शहरी भारत में अधिक बेरोजगार मिले हैं।

आपको बता दें कि ग्रामीण भारत में 6.0 फीसदी और 7.70 फीसदी शहरी बेरोजगारी दर को आंका गया है। कोविड महामारी के दौरान यह बेरोजगारी दर 8 फीसदी थी। तो उस हिसाब से बीते दशक में यह सबसे अधिक बेरोजगारी है। जहां देश के तमाम बेरोजगार युवाओं और छात्रों में स्किल्स की कमी देखी गई। ऐसे में देश के युवा डिजिटल स्किल सीखकर डिजिटल सेक्टर में शानदार कॅरिअर बना सकते है।

सैलरी

मैकिंजी ग्लोबल इंस्टीट्यूट के मुताबिक इस साल युवाओं के लिए डिजिटल सेक्टर के अंदर 6.5 करोड़ नौकरियां उपलब्ध होंगी। वहीं साल 2026 तक भारतीय डिजिटल इंडस्ट्री के 160 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसे में देश के युवा डिजिटल स्किल्स को बढ़ाने के लिए एडवांस डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर सकते हैं। इस कोर्स को आप अपने घर पर बैठकर कर सकते हैं। वहीं इस कोर्स में एक खासियत यह भी है कि इस कोर्स को करने के लिए आपको किसी भी तरह की डिग्री आदि की आवश्यकता नहीं होगी।

पद और सैलरी

डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर- 45 हजार
सोशल मीडिया मैनेजर- 35 हजार
ईमेल मार्केटिंग मैनेजर- 30 हजार
पीपीसी एक्सपर्ट्स- 40 हजार
गूगल एड एक्सपर्ट्स- 50 हजार
इनबाउंड मार्केटिंग- 35 हजार
एसईओ मैनेजर- 40 हजार
कंटेंट मार्केटर- 40 हजार
ब्रांड मैनेजर- 60 हजार
कंटेंट राइटर- 30 हजार

एडवांस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की खासियत

- इस कोर्स में 100 प्रतिशत जॉब प्लेसमेंट असिस्टेंस
- 20 से ज्यादा लर्निंग टूल्स
- गूगल सर्टिफाइड अनुभवी फैकल्टी द्वारा प्रशिक्षण
- 8+ लाइव प्रोजेक्ट्स
- 100 घंटे लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस
- साप्ताहिक डाउट क्लीयरिंग सेशन
- एक्सपर्ट्स के साथ मास्टर क्लास
- कम्प्लीमेंट्री कोर्स-सॉफ्ट स्किल्स

अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं, लेकिन अपने कॅरियर को लेकर परेशान हैं। तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे एडवांस डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर किसी भी एक फील्ड को अपना प्रोफेशन बना सकते हैं। इस कोर्स में ग्राफिक डिजाइनिंग और डिजिटल मार्केटिंग के अलावा भी कई अन्य कोर्स मौजूद है।

अब विदेश में पूरा होगा पढ़ाई का सपना मिलेगी स्कॉलरशिप

जो भी स्टूडेंट आर्ट्स एंड सोशल साइंस में विश्वविद्यालय से यूजी प्रोग्राम करना चाहते हैं, तो वह फैकल्टी ऑफ आर्ट्स ऐंड सोशल साइंसेस इंटरनैशनल अंडरग्रैजुएट कमेंसिंग स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं।

बहुत सारे छात्र विदेश में पढ़ने के इच्छुक होते हैं। ऐसे में अगर आप भी विदेश में पढ़ने का सपना रखते हैं, तो यह आर्टिकल आपके लिए है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी में पढ़ने के इच्छुक अंतरराष्ट्रीय स्टूडेंट के लिए यूनिवर्सिटी ने खास स्कॉलरशिप प्रोग्राम जारी किया है। ऐसे में जो भी स्टूडेंट आर्ट्स एंड सोशल साइंस में विश्वविद्यालय से यूजी प्रोग्राम करना चाहते हैं, तो वह फैकल्टी ऑफ आर्ट्स ऐंड सोशल साइंसेस इंटरनैशनल अंडरग्रैजुएट कमेंसिंग स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, इस प्रोग्राम के तहत छात्रों को कोर्स की अवधि के दौरान AUD 5,000 रुपए हर साल दिए जाएंगे। आपको बता दें कि AUD 5,000 भारतीय मुद्रा में 2,45,389.43 रुपए होता है। आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस प्रोग्राम के तहत आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं।

ऐसे करें अप्लाई

- इस प्रोग्राम के लिए यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट की एप्लिकेशन सर्च करें।
- फिर एप्लिकेशन का लिंक खोलने के बाद उसमें पूछी गई जानकारी और डॉक्यूमेंट्स को अटैच करें।
- इसके बाद फाइनल सबमिट करने से पहले पूरी जानकारी को अटैच्ड डॉक्यूमेंट्स को अच्छी तरह से जांच लें।

कैसे होगा सिलेक्शन

- इस स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्शन का मुख्य आधार मेरिट बेसिस पर होगा। अंक और पर्सेंट के आधार पर स्टूडेंट को स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए चुना जाएगा।

टर्म्स और कंडीशन

- बता दें कि स्कॉलरशिप की तय राशि साल के दो सेमेस्टर में आधा-आधा दिया जाएगा।
- हर सेमेस्टर में स्टूडेंट को कम से कम 65% एवरेज मार्क्स लाना होगा।
- स्कॉलरशिप खारिज होने के बाद फिर से बहाल नहीं किया जाएगा। जब तक ऐसा यूनिवर्सिटी की गलती से न हुआ हो।
- स्कॉलरशिप के अलावा अन्य कोई भी अमाउंट स्टूडेंट को नहीं दिया जाएगा।

पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी में गोल्डन करियर

ऊर्जा का अहम स्त्रोत होने के नाते पेट्रोलियम की उपयोगिता से सभी वाकिफ है। भारत पेट्रोलियम पदार्थों की अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा विदेश से आयात करता है। अगर आंकड़ों की मानें तो पेट्रोलियम पदार्थों के उपयोग में भारत विश्व का आठवां बड़ा देश है। एचपीसीएल, बीपीसीएल, रिलायंस, इंडियन ऑयल जैसी कंपनियों से सरकार को भारी-भरकम राजस्व मिलता है।

संभावनाएं

पहले इस क्षेत्र में जियोलॉजिस्ट की काफी मांग थी, समय बदलने के साथ मैकेनिकल क्षेत्र के विशेषज्ञों ने इस इंडस्ट्री में अपनी धाक जमाई। करियर की अनेक संभावनाओं को देखते हुए इस क्षेत्र में प्रबंधन से लेकर इंजीनियरिंग तक के कोर्स शुरू हुए हैं। पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी ने बीबीए, एमबीए, एमटेक, बीटेक, एमएससी जैसे कोर्स शुरू किए है। इसके अलावा देश के चुनिंदा संस्थानों ने पेट्रोलियम के क्षेत्र में बीई, बीटेक, एमई, एमटेक, एमएससी और बीएससी जैसे कोर्स शुरू किए हैं। ये सभी कोर्स पेट्रोकैमिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोटेक्नोलॉजी, गैस इंजीनियरिंग, पेट्रोमार्केटिंग आदि में शुरू किए हैं।

स्टडी कोर्स

पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में छात्र जियोलॉजी, भौतिकी और इंजीनियरिंग के सिद्धांतों द्वारा पेट्रोलियम की रिकवरी, डेवलपमेंट और प्रोसेसिंग के बारे में जानते हैं। इसके अलावा ड्रिलिंग, मैकेनिक्स, पर्यावरण संरक्षण और पेट्रोलियम जैसे विषयों पर छात्रों की पकड़ बनाई जाती है। पेट्रोलियम इंडस्ट्री को मुख्य तौर पर दो भागों में बांट कर देख सकते है- अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम सेक्टर। अपस्ट्रीम सेक्टर में खोज, उत्पादन व तेल और प्राकृतिक गैसों का दोहन कैसे किया जाए, इसकी शिक्षा व ट्रेनिंग दी जाती है। डाउनस्ट्रीम सेक्टर में रिफाइनिंग, मार्केटिंग और वितरण से संबंधित पूरी जानकारी दी जाती है। पेट्रोलियम के क्षेत्र में टीम की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है। एक पेट्रोलियम इंजीनियर को जियोलॉजिस्ट, अन्वेषणकर्ता, इंजीनियर, पर्यावरण क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ काम करना पड़ता है।

योग्यता

बारहवीं की परीक्षा भौतिक विज्ञान, गणित और रसायन विज्ञान से 50 प्रतिशत अंकों से पास करने के बाद आप इस कोर्स के लिए आवेदन कर सकते है। केमिकल और पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में बीई और बीटेक कर चुके छात्र पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में एमटेक के लिए आवेदन कर सकते हैं। बीबीए में प्रवेश के लिए बारहवीं किसी भी संकाय से उत्तीर्ण होना जरूरी है।

अवसर

पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नौकरी की अपार संभावनाएं मौजूद है। लगभग आठ लाख लोगों को रोजगार देने वाला यह क्षेत्र अवसरों से भरा पड़ा है। हिन्दुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, रिलायंस, ओएनजीसी, पेट्रोनेट जैसी नामी-गिरामी कंपनियों के द्वार आपके लिए खुले हैं। जिस तरह पेट्रोल के नए भंडार और क्षेत्र मिल रहे हैं, उससे यह क्षेत्र आने वाले समय में बड़ा लाभकारी साबित होगा।

कलिंग समाचार

संपादकीय

रविवार 08 मार्च 2026

सांप्रदायिकता की आंच में तपती देवभूमि

हमारा देश जब लोकतंत्र की स्थापना के 78वें वर्ष की ओर कदम बढ़ा रहा था, तब देवभूमि कहे जाने वाले उसके ही एक प्रान्त में एक सदी से भी ज़्यादा पुरानी विरासत पर भद्दी गालियों, जय श्रीराम और बजरंग बली की जय जैसे आक्रामक नारों के साथ हथौड़े और सब्बल चलाये जा रहे थे, वहां रखे धार्मिक ग्रंथों को नुकसान पहुंचाया जा रहा था और धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश की जा रही थी। दरअसल, मसूरी के एक मिशनरी स्कूल की निजी ज़मीन पर स्थित बाबा बुल्ले शाह की मजार बहुसं यक गुंडागर्दी की बलि चढ़ गई। उसके साथ मौजूद दो अन्य मज़ारों को भी तोड़ दिया गया, वहीं दानपेटी को तोड़कर नकदी निकाल ली गई। भाईचारे और सौहार्द्र का प्रतीक रही बुल्ले शाह की मज़ार के परिसर में रविवार की शाम मुट्ठी भर हिन्दूवादी जूते पहनकर घुस गये और अपने घटिया इरादों को अंजाम दिया। इस घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल बन गया। मसूरी पुलिस ने तीन नामजद आरोपियों सहित 25-30 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस बीच हिन्दू रक्षा दल के अध्यक्ष भूपेंद्र उर्फ पिंकी चौधरी ने अपने संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा इस तोडफ़ोड़ की ज़ि मेदारी ली है। पुलिस कब और कैसे इस दावे का संज्ञान लेती है, देखना होगा। हालांकि इस पूरे प्रकरण में राहत की बात ये रही कि पुलिस में शिकायत करने जाने वालों में केवल मुस्लिम संगठन ही नहीं, दूसरे समुदायों के लोग भी शामिल थे। बाबा बुल्ले शाह- जिन्हें बुल्लेया कहकर भी संबोधित किया जाता है, एक क्रांतिकारी दार्शनिक, समाज सुधारक और कवि थे, जिन्हें पंजाबी भाषा के महानतम कवियों में से एक माना जाता है और जिनका स मान पंजाबी ज्ञानोदय के जनक% के रूप में है। उनका असल नाम सैयद अब्दुल्लाह शाह कादरी था और उन्हें हजऱत मुहमद साहब की पुत्री फातिमा का वंशज माना जाता है। उनके पिता शाह मुह मद थे जिन्हें अरबी, फारसी और कुरान शरीफ़ का अच्छा ज्ञान था। पिता के नेक जीवन का प्रभाव बुल्ले शाह पर भी पड़ा और शायद इसीलिए सैयद यानी ऊंची जाति से होते हुए भी उन्होंने निचली जाति आराइन के शाह इनायत को अपना गुरु बनाया। हिन्दी और पंजाबी में अनगिनत गीत बुल्ले शाह की रचनाओं पर आधारित हैं या उनमें बुल्ले शाह का हवाला है। 1970 के दशक में नरेंद्र चंचल का गाया गीत- बेशक मंदिर-मस्जिद तोड़ो, बुल्ले शाह ये कहता / पर प्यार भरा दिल कभी न तोड़ो, जिस दिल में दिलबर रहता हरेक किशोर और युवा की ज़बान पर हुआ करता था। लगभग दो दशक पहले मशहूर पंजाबी गायक रब्बी शेरगिल ने बुल्ला की जाणा मैं कौन% गाकर तारीफें हासिल की तो करीब एक दशक पहले रणबीर कपूर पर फिल्माया गया यार बुल्लेया गीत भी काफ़ी लोकप्रिय हुआ। दमादम मस्त कलंदर तो बाबा बुल्ले शाह की सदाबहार रचना है ही। लेकिन धर्म का इकहरा और बेसुरा राग अलापने वाले जाहिल क्या जानें कि कविता क्या होती है और उसे संगीत में पिरोना क्या होता है, बुल्ले शाह की रचनाओं और उनके दर्शन को समझना तो बहुत दूर की बात है। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि बुल्ले शाह की मज़ार पर हमला सुनियोजित ढंग से किया गया हो। ताज्जुब है कि एक हिन्दूवादी संगठन खुलकर इस हमले की जि मेदारी ले रहा है, लेकिन उसकी भनक तक पुलिस को नहीं लगी। क्या यह सीधे-सीधे पुलिस के निगरानी और सूचना तंत्र की असफलता नहीं है। वैसे, उत्तराखंड जिस तेजी से हिन्दुत्व की प्रयोगशाला बनता जा रहा है, उसे देखकर यह माना जा सकता है कि धर्म के नाम पर उपद्रव करने वालों को कहीं न कहीं से शह मिल रही है और कानून-व्यवस्था बनाये रखने के लिये ज़ि मेदार केवल खानापूरी कर रहे हैं। सबरंग इंडिया वेबसाइट ने इस पहाड़ी प्रदेश में हुई सांप्रदायिक घटनाओं पर नागरिक अधिकारों के संरक्षण के लिए गठित संघ (एपीसीआर) की तथ्यान्वेषी रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसमें 2021 और 2025 के बीच उत्तराखंड के कई जिलों में मुसलमानों को प्रभावित करने वाली सांप्रदायिक हिंसा, धमकी, बेदखली, विस्थापन और उनके धर्मस्थलों पर हमले की घटनाओं की एक श्रृंखला का दस्तावेजीकरण किया गया है।

जलवायु-परिवर्तन से जीत सकती हैं महिलाएं

अपूर्वा श्रीवास्तव

महिलाएं शिक्षित और जागरूक होंगी, तो वे प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को बेहतर ढंग से समझ पाएंगी। वे जनसं या वृद्धि, स्वास्थ्य संबंधी निर्णयों और घरेलू निर्णय-प्रक्रिया में अधिक सक्रिय भूमिका निभा सकेंगी। इसके साथ ही वे उपभोग के पैटर्न में भी सकारात्मक बदलाव ला सकती हैं। खाद्य, ऊर्जा और अन्य संसाधनों के उपयोग के संबंध में वे अधिक समझदारी और संतुलन के साथ निर्णय लेने में सक्षम होंगी।

महिलाओं के लिए ऐसा वातावरण बनाया जाए कि वे सुरक्षित रह सकें - यह वाक्य हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन आए दिन ऐसी घटनाएँ सामने आती हैं जो महिलाओं को असुरक्षित महसूस कराने के लिए पर्याप्त हैं। %राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो% (एनसीआरबी) के आँकड़े भी महिलाओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा की ओर संकेत करते हैं। जब हम महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं तो यह केवल सामाजिक सुरक्षा का प्रश्न नहीं रह जाता, बल्कि उस व्यापक वातावरण से भी जुड़ जाता है जिसमें हम सभी रहते हैं।

वातावरण हमारे चारों ओर का वह परिवेश है जिसमें सभी जैविक और अजैविक तत्व शामिल हैं। यह वही बाहरी घेरा है जो हमारे जीवन, व्यवहार और विकास को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, जिसे अक्सर पर्यावरण भी कहा जाता है। आज यह वातावरण संतुलित नहीं रह गया है। तापमान बढ़ रहा है और जलवायु परिवर्तन की प्रक्रिया तेज हो रही है। इसका खामियाजा भी भेदभाव से भरा हुआ है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन जेंडर-न्यूट्रल नहीं है। यानी इसके नकारात्मक प्रभाव महिलाओं पर सबसे अधिक पड़ते हैं। कई मायनों में जलवायु परिवर्तन मानवीय अधिकारों को भी पीछे धकेल देता है।

जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो महिलाओं के खिलाफ अत्याचार नाटकीय रूप से बढ़ जाते हैं। उदाहरण के लिए बाढ़ में महिलाओं की मृत्यु अधिक होती है क्योंकि उन्हें जिन्दा रहने के कौशलों की ट्रेनिंग नहीं दी जाती। ग्रामीण परिवेश में महिलाओं को खेल-कूद से दूर रखा जाता है। महिलाओं के खानपान का कम याल रखा जाता है जिसके चलते भोजन में जरूरी पोषक तत्वों की कमी हमेशा होती है। परिवारों में वे आखिर में खाना खाती हैं। इस तरह की सामाजिक संरचनाएँ संकट के समय में उनकी स्थिति को और कमजोर बना देती हैं। स्पष्ट है, जलवायु परिवर्तन की मार महिलाओं पर अधिक पड़ रही है।

गर्मी, सूखा, तूफान और बाढ़ जैसी आपदाओं की वजह से महिलाओं को ज्यादा मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं। 1991 में बांग्लादेश में आए चक्रवाती तूफान में मरने वालों में लगभग 91 प्रतिशत महिलाएं थीं। इसका एक कारण यह भी था कि उनमें से बहुत सी महिलाएं तैरना नहीं जानती थीं। तैरना इसलिए नहीं जानती थीं, क्योंकि वे घर के भीतर ही रहती थीं और अकेले बाहर जाने की अनुमति नहीं होती थी। इसी तरह 2003 में यूरोप में जब भीषण हीट-वेव आई, मरने वालों में महिलाओं की सं या सबसे अधिक थी। महिलाओं की मृत्यु-दर पुरुषों की तुलना में डीहाइड्रेशन और हृदय संबंधी समस्याओं के कारण लगभग 15-20 प्रतिशत अधिक थी। ज़्यादा जानें समाचार पत्र विज्ञापन ताज़ा ख़बरें सूचना समाचार बुलेटिन जलवायु परिवर्तन के कारण महिलाओं पर हिंसा भी बढ़ती है। कई द्वीपीय देशों में चक्रवाती तूफानों के बाद घरेलू हिंसा के मामलों में वृद्धि देखी गई है। कई स्थानों पर अस्थायी राहत शिविरों में भी महिलाओं को कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। अफ्रीका के कुछ क्षेत्रों में मौसम के चलते फसल खराब होने के बाद परिवारों द्वारा लड़कियों को बेचकर मवेशी खरीदने जैसी घटनाएं भी सामने आई हैं। दक्षिण केन्या में फिश फॉर सेक्स जैसी प्रथा का उल्लेख मिलता है, जहां मछली के बदले लड़कियों का शारीरिक शोषण किया जाता है। एक स्वीडिश अध्ययन के अनुसार पुरुष औसतन केवल दो प्रतिशत अधिक कार्बन उत्सर्जन के लिए वे लगभग 16 प्रतिशत अधिक जि मेदार होते हैं। इसका कारण यह है कि पुरुष अधिक बाहर निकलते हैं और पेट्रोल-डीजल का अधिक उपयोग करते हैं, जिससे %ग्रीनहाउस गैसों% का उत्सर्जन बढ़ता है। जलवायु परिवर्तन के चलते और गहरी होती लैंगिक असमानता को समझना जरूरी है। उड़ीसा में आए एक साइक्लोन की केस-स्टडी में सामने आया कि प्राकृतिक आपदा के बाद आर्थिक संकट के कारण एक परिवार ने अपनी बेटी को नौकरी के लिए बाहर भेज दिया, लेकिन बाद में पता चला कि उसे बांग्लादेश में बेच दिया गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि साइक्लोन के कारण उनकी कृषि भूमि लगभग 10 साल के लिए उपज के लायक नहीं बची थी। वहीं महाराष्ट्र में %वॉटर वाइफ% यानी %पानी-बाई% देखने मिलतीं हैं, जिसमें पानी भरने के लिए पुरुष कई महिलाओं से विवाह करते हैं। यह जलवायु संकट से जुड़ा एक सामाजिक और लैंगिक अन्याय है। ज़्यादा जानें राजनीतिक विश्लेषण रिपोर्ट खेल समाचार ऐप ई-पेपर सदस्यता ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर पुरुष रोजगार के लिए शहरों की ओर चले जाते हैं। ऐसे में परिवार, खेती और बुजुर्गों की जि मेदारी महिलाओं पर आ जाती है। इसलिए यह और भी जरूरी हो जाता है कि उन्हें जलवायु परिवर्तन से बचाने के उपाय किए जाएं। एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि लगभग 33 प्रतिशत महिलाएं कृषि कार्य से जुड़ी हुई हैं, लेकिन उनमें से केवल 15 प्रतिशत के पास ही जमीन का मालिकाना अधिकार है। इकोफेमिनिज्म पुस्तक की लेखक, पर्यावरणविद् वंदना शिवा ने जलवायु परिवर्तन पर विस्तार से लिखा है। उनका कहना है कि %ग्लोबल साउथ% की महिलाएं केवल पर्यावरण विनाश से पीड़ित नहीं हैं, बल्कि वे पर्यावरण की अग्रिम पंक्ति की रक्षक भी हैं। वंदना शिवा कहती हैं कि जिसे हम आधुनिक विज्ञान कहते हैं, वह इतिहास के एक छोटे से दौर में विकसित हुआ एक संकीर्ण पितृसत्तात्मक प्रोजेक्ट है। आधुनिक विज्ञान की यह धारा प्रकृति को एक यांत्रिक और शोषण योग्य वस्तु के रूप में देखती है। औद्योगिक क्रांति के समय ऐसी ज्ञान-प्रणाली विकसित हुई जिसने प्रकृति के दोहन को बढ़ावा दिया। इसके विपरीत संरक्षण, पुनर्जीवन और संतुलन से जुड़ा ज्ञान, जो अक्सर महिलाओं, किसानों, आदिवासियों और स्थानीय समुदायों के पास था, उसे हाशिए पर डाल दिया गया। समस्याओं से बचने का सबसे महत्वपूर्ण उपाय शिक्षा है, लेकिन यहां केवल सामान्य या जेनेरिक शिक्षा की बात नहीं हो रही, बल्कि ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जो जलवायु से जुड़ी हो। लोगों को अपने स्थानीय जलवायु, भूगोल और पर्यावरण की समझ होना बेहद जरूरी है। जब व्यक्ति अपने आसपास के पर्यावरण को समझेगा, तभी वह उसके संरक्षण के लिए जि मेदार व्यवहार भी अपनाएगा। जलवायु आधारित शिक्षा केवल किसी एक वर्ग के लिए नहीं, बल्कि समाज के हर तबके और हर उम्र के लोगों के लिए आवश्यक है। ज़्यादा जानें चुनावी जागरूकता अभियान बॉलीवुड समाचार सेवा चुनावी सर्वेक्षण उपकरण जलवायु परिवर्तन की समस्या को कम करने के लिए बड़े स्तर पर जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता है। इसे केवल चर्चा का विषय बनाकर छोड़ देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसे प्राथमिकता के साथ लागू करने की जरूरत है। इसके साथ ही लोगों के व्यवहार में भी आमूलचूल बदलाव लाना जरूरी है। संसाधनों का समझदारी से उपयोग करना, ऊर्जा की बचत करना और पर्यावरण के प्रति जि मेदार रवैया अपनाना एक जागरूक नागरिक की जि मेदारी होनी चाहिए। ऐसा करने से न केवल वर्तमान समाज को लाभ होगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी सुरक्षित भविष्य मिल सकेगा। महिलाओं की बुनियादी शिक्षा, उनके खान-पान और खेलकूद पर पर्याप्त ध्यान दिया जाए तो वे शारीरिक रूप से मजबूत बन पातीं हैं। महिलाएं शिक्षित और जागरूक होंगी, तो वे प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को बेहतर ढंग से समझ पाएंगी। वे जनसं या वृद्धि, स्वास्थ्य संबंधी निर्णयों और घरेलू निर्णय-प्रक्रिया में अधिक सक्रिय भूमिका निभा सकेंगी। इसके साथ ही वे उपभोग के पैटर्न में भी सकारात्मक बदलाव ला सकती हैं। खाद्य, ऊर्जा और अन्य संसाधनों के उपयोग के संबंध में वे अधिक समझदारी और संतुलन के साथ निर्णय लेने में सक्षम होंगी। महिलाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण न केवल समाज में लैंगिक समानता को बढ़ावा देगा, बल्कि जलवायु परिवर्तन से निपटने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मेलिंडा गेट्स ने अपनी किताब %द मूमेंट यू लि ट - हाउ एंपावरिंग वुमेन चेंज द वर्ल्ड% में कहा है, %जब आप एक महिला को ऊपर उठाते हैं तो पूरी मानवता ऊपर उठती है।

पैसे से पिछड़ता न्याय

अमरपाल सिंह वर्मा

देश की जेलों में आज भी बड़ी सं या में ऐसे कैदी बंद हैं जिन्हें अदालतें जमानत या पैरोल दे चुकी हैं, लेकिन पैसे के अभाव में वे सलाखों के पीछे पड़े हैं। कई ऐसे भी हैं जिनकी सजा की अवधि पूरी हो चुकी है मगर जुर्माना भरने में असमर्थ होने के कारण उन्हें रिहाई नहीं मिल पा रही। इस तरह कानून की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद भी कैद केवल इसलिए जारी रहती है क्योंकि वह व्यक्ति गरीब है। राजस्थान हाईकोर्ट ने हाल में उम्रकैद की सजा भुगत रहे एक कैदी खरताराम की चिट्ठी को याचिका मानकर सुनाए गए अपने फैसले में कहा है कि गरीबी कोई अपराध नहीं है और न ही यह किसी व्यक्ति को उसके अधिकारों से वंचित करने का आधार बन सकती है। पाली जिले का निवासी खरताराम हत्या के एक मामले में 2014 से सजा काट रहा है।

%जिला पैरोल कमेटी% ने 29 सितंबर 2025 को उसे चौथी बार 40 दिन की नियमित पैरोल पर रिहा करने का आदेश दिया, लेकिन इसके साथ 25-25 हजार रुपए के दो जमानती पेश करने की शर्त जोड़ दी गई।

आर्थिक रूप से बेहद कमजोर होने के कारण खरताराम यह शर्त पूरी नहीं कर सका। उसके पास वकील तक के पैसे नहीं थे, इसलिए उसने जेल से ही पोस्टकार्ड भेजकर हाईकोर्ट से गुहार लगाई। हाईकोर्ट ने न केवल उसकी याचिका सुनी, बल्कि इस फैसले को ऐसे मामलों में एक नजीर के रूप में स्थापित कर दिया। अदालत ने स्पष्ट कहा कि पैरोल या जमानत की शर्तें तय करते समय अधिकारियों को मशीनी रवैया छोड़कर मानवीय और संवैधानिक दृष्टि अपनानी होगी। यह फैसला केवल एक कैदी को राहत देने तक सीमित नहीं है, बल्कि उस व्यापक समस्या की ओर इशारा करता है जिसमें देश के हजारों गरीब कैदी फंसे हुए हैं। सवाल केवल पैरोल का नहीं है। सवाल उस व्यापक ढांचे का है, जहां जमानत, पैरोल और अर्थदंड जैसे कानूनी प्रावधान गरीब व्यक्ति के लिए राहत नहीं, बल्कि नई सजा बन जाते हैं।

देश की जेलों में आज भी बड़ी सं या में ऐसे कैदी बंद हैं जिन्हें अदालतें जमानत या पैरोल दे चुकी हैं, लेकिन पैसे के अभाव में वे सलाखों के पीछे पड़े हैं। कई ऐसे भी हैं जिनकी सजा की अवधि पूरी हो चुकी है मगर जुर्माना भरने में असमर्थ होने के कारण उन्हें रिहाई नहीं मिल पा रही।

इस तरह कानून की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद भी कैद केवल इसलिए जारी रहती है क्योंकि वह व्यक्ति गरीब है। इसका सबसे सीधा असर जेलों पर पड़ता है। जेलें अपनी निर्धारित क्षमता से कहीं अधिक भरी हुई हैं। विचाराधीन बंदियों की सं या बहुत अधिक है। जेलों में भीड़ के कारण कम जगह तथा सीमित संसाधनों का परिणाम खराब स्वास्थ्य सुविधाओं के रूप में आता है। जेलों में अपराधियों को रखने के पीछे सुधार का मूल उद्देश्य भटक चुका है। यह समस्या कितनी गंभीर है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 26 नवंबर 2022 को %संविधान दिवस% के अवसर पर स्वयं राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू को कहना पड़ा कि देश की जेलों में हजारों ऐसे कैदी बंद हैं जिनके पास जमानत पर रिहाई का कोर्ट आदेश तो है, लेकिन जमानत राशि के पैसे नहीं हैं। उन्होंने अदालतों और सरकार से इन कैदियों के लिए समाधान निकालने की अपील की थी। राष्ट्रपति की इस टिप्पणी के दो दिन बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने स्वत- संज्ञान लेते हुए केंद्र और राज्यों से रिपोर्ट तलब कर ली। इसके बाद फरवरी 2023 में सर्वोच्च अदालत ने इस मुद्दे पर सात महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए। अदालत की मंशा साफ है कि जमानत आदेश की सार्थकता तभी है, जब वह वास्तव में किसी को जेल से बाहर ला सके। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश एक रिपोर्ट में सामने आया कि जनवरी 2023 तक 5,380 ऐसे कैदी थे, जिन्हें जमानत मिल चुकी थी, लेकिन वे अब भी जेलों में बंद थे। इन मामलों की वजह पैसे का अभाव ही था। 2023 में ही सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल अदालतों को निर्देश दिए कि वे जमानत की शर्तें तय करते समय कैदियों की आर्थिक स्थिति पर भी विचार करें। अदालत ने साफ शब्दों में कहा कि अगर जमानत की शर्तें कैदी की हैसियत से परे हैं तो ऐसी जमानत का कोई अर्थ नहीं रह जाता। राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला भी इसी सोच की अगली कड़ी है। सुप्रीम कोर्ट की इसी संवैधानिक सोच का अनुसरण करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने अब यह महत्वपूर्ण फैसला दिया है। इसमें हाईकोर्ट ने माना है कि पैरोल एक सुधारात्मक अधिकार है, यह अमीरों का विशेषाधिकार नहीं है। कोर्ट ने अधिकारियों की उस प्रवृत्ति पर कड़ी नाराजगी जताई है, जिसमें हर मामले में एक जैसी जमानत शर्तें थोप दी जाती हैं। यह भी नहीं देखा जाता कि कैदी उन्हें पूरा करने की स्थिति में है या नहीं। हाईकोर्ट द्वारा जारी की गई छह सूत्रीय गाइडलाइन से इस बात का संकेत मिलता है कि अदालतें अब केवल आदेश देने तक सीमित नहीं रहना चाहतीं, बल्कि उसके प्रभावी क्रियान्वयन पर भी बल देना चाहती हैं। अदालतें बार-बार निर्देश दे रही हैं, लेकिन बड़ा सवाल है कि नीतियों और आदेशों का क्रियान्वयन क्यों नहीं हो पा रहा? सुप्रीम कोर्ट पहले ही अनावश्यक गिर तारी, रिमांड और जमानत के बावजूद जेल में बंद रखने की प्रवृत्ति पर नाराजगी जता चुका है। कोर्ट ने गरीब कैदियों की मदद के लिए एक मानक प्रक्रिया और फंड की व्यवस्था की बात भी कही है, लेकिन अधिकांश राज्यों में यह पहल अमल तक पहुंचने के इंतजार में है। हाल में हरियाणा सरकार ने फैसला किया है कि वह गरीब कैदियों को जमानत या जुर्माना भरने में आर्थिक सहायता देगी। जमानत के लिए एक लाख रुपये तक और जुर्माने के लिए 25 हजार रुपये तक दिए जाएंगे। यह एक सकारात्मक कदम है जिसे अपवाद नहीं बल्कि नियम बनाया जाना चाहिए। सभी राज्यों को ऐसी योजनाएं लागू करनी होंगी। जमानत और पैरोल की शर्तें तय करते समय आर्थिक स्थिति का वास्तविक आकलन होना चाहिए। जिला स्तर पर ऐसे तंत्र विकसित करने की जरूरत है, जो यह सुनिश्चित करें कि किसी व्यक्ति को केवल गरीबी के कारण जेल में न रहना पड़े। गरीब कैदी अपनी बात अदालत तक पहुंचा सकें, यह सुनिश्चित करने के लिए कानूनी सहायता सेवाओं को मजबूत करना होगा। ऐसा जरूरी नहीं कि हर जज किसी कैदी के पोस्टकार्ड को याचिका मान ले। जेलों को दंड के नहीं बल्कि सुधार के स्थान के रूप में देखने की सोच विकसित करने की जरूरत है। ऐसा होने पर ही अदालती फैसलों को सही मायने में क्रियान्वित किया जा सकेगा। समाधान साफ हैं, बस इच्छाशक्ति की जरूरत है।

विविध समाचार

खटकता था प्रेमिका का मासूम बेटा, क्रेच से अगवा कर ऑटो में घोंट दिया गला, 3 दिन पहले ही मनाया था पहला जन्मदिन

पंचकूला ०७/०३ (संवाददाता): हरियाणा के पंचकूला से ममता और इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। अवैध संबंधों के चलते एक शख्स ने अपनी प्रेमिका के महज एक साल के मासूम बेटे की निर्मम हत्या कर दी। इस घटना की भयावहता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अभी तीन दिन पहले ही बच्चे का पहला जन्मदिन मनाया गया था। आरोपी को अपनी प्रेमिका के साथ बच्चे का होना पसंद नहीं था, इसलिए उसने साजिश रचकर पहले बच्चे को क्रेच (डे–केयर सेंटर) से अगवा किया और फिर ऑटो में गला दबाकर उसकी जान ले ली। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और बच्चे का शव झाड़ियों से बरामद कर लिया गया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि डेराबस्सी की रहने वाली एक महिला का पिंजौर निवासी युवक के साथ अफेयर चल रहा था। महिला जब भी अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती थी, तो अपने बेटे रेयांश को साथ ले जाती थी। आरोपी को अपनी प्रेमिका के साथ बच्चे की मौजूदगी बिल्कुल पसंद नहीं थी और वह उसे अपने रिश्ते में बाधा मानता था। इसी वजह से उसने बच्चे को रास्ते से हटाने की खौफनाक योजना बनाई। आरोपी ने ही महिला को सलाह दी थी कि वह बच्चे को क्रेच में डाल दे, ताकि वे एकांत में समय बिता सकें। शातिर आरोपी करीब 15 दिन पहले खुद महिला के साथ जाकर सेक्टर–12। के उस क्रेच की रेकी भी करके आया था। योजना के मुताबिक, महिला ने बीते दिन (24 जनवरी) बच्चे को पहली बार सेक्टर–12। के क्रेच में भर्ती करवाया। लेकिन इसके कुछ ही देर बाद सुबह करीब 11 बजे आरोपी वहां पहुंच गया। उसने क्रेच संचालिका को झूठ बोला कि वह बच्चे का पिता है और उसे ले जाने आया है। संचालिका ने पुष्टि के लिए बच्चे की मां को फोन किया, लेकिन फोन स्विच ऑफ होने के कारण बात नहीं हो सकी।

इस पर संचालिका ने भरोसा करके बच्चा आरोपी को सौंप दिया। क्रेच से बच्चे को लेकर आरोपी ऑटो से पिंजौर की ओर निकल गया। रास्ते में जब मासूम अपनी मां के लिए रोने लगा, तो आरोपी ने गुस्से में आकर चलती ऑटो में ही उसका गला दबा दिया। हत्या के बाद उसने शव को एक बोरी में भरकर सुखोमाजरी बाईपास के पास झाड़ियों में फेंक दिया। एएनसी टीम इंचार्ज एएसआई प्रवीन ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और शुरुआती पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। हालांकि, पुलिस कस्टडी में वह बार–बार अपने बयान बदल रहा है। कभी वह कहता है कि बच्चे के रोने पर उसे गुस्सा आ गया था इसलिए मारा, तो कभी कहता है कि वह महिला से पीछा छुड़ाना चाहता था और उसे डराने के लिए बच्चे को अगवा किया था। पुलिस आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेगी ताकि हत्या के वास्तविक कारणों और साजिश की पूरी गहराई तक पहुंचा जा सके। पुलिस ने बताया कि आरोपी और मृतक की मां के बीच अफेयर की पुष्टि हो चुकी है।

सोनीपत में प्रधानमंत्री रोजगार मेले का आयोजन, चयनित युवाओं को सरकारी सेवाओं में नियुक्ति पत्र वितरित

चंडीगढ ०७/०३ (संवाददाता): प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की देश के युवाओं को सरकारी नौकरी देने की संकल्प सिद्धि की दिशा में आज दिनांक 24 जनवरी 2026 (शनिवार) को राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री रोजगार मेले के 18वें संस्करण का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने रिमोट का बटन दबाकर देशभर के 45 स्थानों पर चयनित 61,656 युवक–युवतियों, जिनमें 8,000 से अधिक नारी शक्ति शामिल हैं, को विभिन्न सरकारी विभागों में नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस अभियान के अंतर्गत ग्रुप केन्द्र, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सी.आर.पी.एफ.), खेवड़ा, सोनीपत में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों, विशेष रूप से अर्धसैनिक बलों में चयनित 103 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण खेवड़ा स्थित सी.आर.पी.एफ. समूह केन्द्र में किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री, भारत सरकार, श्री कृष्ण पाल गुर्जर उपस्थित रहे, जिन्होंने चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। देशभर में आयोजित रोजगार मेलों के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के उद्बोधन का सीधा प्रसारण किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री श्री कृष्ण पाल गुर्जर ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सदैव रोजगार सृजन, नवाचार, तकनीक के उपयोग और नागरिकों को विकास के केंद्र में रखने पर बल दिया है। नवनियुक्त अभ्यर्थियों को पळव्ज कर्मयोगी पोर्टल पर 'कर्मयोगी प्रारंभ' ऑनलाइन मॉड्यूल के माध्यम से प्रशिक्षण का अवसर भी प्रदान किया जा रहा है, जहां 1,588 से अधिक ई–लर्निंग पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। यह प्रशिक्षण युवाओं को उनकी जिम्मेदारियों को प्रभावी ढंग से निभाने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने के लिए सक्षम बनाएगा। इस अवसर पर सी.आर.पी.एफ. समूह केन्द्र खेवड़ा के पुलिस उप–महानिरीक्षक श्री अजीत सांगवान ने केंद्रीय राज्य मंत्री का अभिनंदन किया तथा नवनियुक्त युवाओं को प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम में श्री अमित कुमार, कमांडेंट–220 बटालियनय श्री दलजीत सिंह भाटी, द्वितीय कमान अधिकारीय श्री वेदपाल, उप कमांडेंट सहित अन्य अधिकारीगण भी उपस्थित रहे। केंद्रीय मंत्री द्वारा सफल एवं भव्य आयोजन के लिए ग्रुप केन्द्र, सी.आर.पी.एफ., सोनीपत की सराहना की गई।

बारिश व तेज हवाओं में भी नहीं गिरा जज्बा, अनिल विज ने नेताजी को किया नमन

चंडीगढ ०७/०३ (संवाददाता): नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती (पराक्रम दिवस) के अवसर पर हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने शुक्रवार को अंबाला छावनी स्थित सुभाष पार्क में नेताजी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। तेज बारिश और हवाओं के बावजूद विज पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ कार्यक्रम में पहुंचे और 12 फुट ऊंची प्रतिमा के समक्ष सैन्य अंदाज में सैल्यूट कर भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ 'नेताजी अमर रहें' के नारे लगाये। इस अवसर पर विज ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जीवन देशभक्ति, साहस और बलिदान की मिसाल है। उन्होंने कहा कि नेताजी के नाम पर अंबाला छावनी में सुभाष पार्क का निर्माण कराया गया है, जहां हर वर्ष उनकी जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित किये जाते हैं। उन्होंने कहा कि जब से यह पार्क बना है और नेताजी की प्रतिमा यहां स्थापित हुई है, तब से लगातार लोग यहां आकर प्रेरणा लेते हैं। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आह्वान पर 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पराक्रम दिवस के रूप में मनायी जाती है। इसी क्रम में अंबाला छावनी में भी श्रद्धा और सम्मान के साथ कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान मंत्री अनिल विज ने भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों के साथ नेताजी को नमन किया और इसके बाद जन्मदिवस के अवसर पर लड्डू भी बांटे। कार्यक्रम में नगर परिषद अध्यक्ष स्वर्ण कौर, भाजपा नेता संजीव सोनी, आशीष अग्रवाल और बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। गौरतलब है कि 17 एकड़ में फैला सुभाष पार्क ऊर्जा मंत्री अनिल विज के प्रयासों से विकसित हुआ है। यह पार्क हरियाणा के सुंदरतम पार्कों में शुमार है, जहां रोजाना बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं और नेताजी के विचारों की प्रेरणा लेते हैं।

मजे के लिए चाइनीज डोर इस्तेमाल करके दूसरों को सजा ना दें : अरुण संदल

जालंधर ०७/०३ (संवाददाता):चाइना डोर आज मौत का दूसरा नाम बन चुकी है। पुलिस प्रशासन कई सालों से प्रयास कर रहा है पर इस पर चाइनीज मौत पर काबू पाना उसके बस में भी नहीं लग रहा। यह कहना है सतगुरु कबीर टाइगर फोर्स के प्रधान अरुण संदल का। इस बारे में उन्होंने कहा कि चाइना डोर हर बार बसंत पर्व पर कई जाने ले लेती है फिर चाहे वो इंसानी हो या फिर पशु–पक्षियों की। इंसानी जान के बारे में अगर बात करें तो अक्सर लोग पतंगें उड़ाने में चाइनिस डोर का इस्तेमाल करते हैं जो पतंग कटने के बाद हर गली–चोराहे पर किसी पेड़ या फिर खंबे से लटकी मिलती है जो आने–जाने वाले राहगीरों के गले में फसने से उनका खासा नुक्सान करती है अभी हाल ही में जालंधर में एक छोटे बच्चे के गले में चाइनीज डोर के कारण गहरा कट लग गया पर समय रहते ही पास खड़े लोग उसे अस्पताल ले गए और उसकी जान बच गई। इसके अलावा हाईटैंशन तारों या फिर बिजली के ट्रांस्फार्मर से अटकी इस मौत की डोर को जब कोई खींच कर उतारने की कोशिश भी करता है तो वो भी इसकी चपेट में आ जाता है और जोरदार झटके से अपना ही नुक्सान कर बैठता है। इसी डोर को खींचते वक्त पता नहीं जाने–अनजाने में कितने जानलेवा कांड हो चुके हैं।

विकास महाजन ने थाईलैंड में बढ़ाया देश का मान, जिमखाना में मिला सम्मान

जालंधर ०७/०३ (संवाददाता): थाईलैंड में आयोजित सिक्स थाईलैंड वरिष्ठ खेल प्रतियोगिता में विकास महाजन ने टेबल टेनिस में शानदार प्रदर्शन कर देश का गौरव बढ़ाया है। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए अनुशासन, समर्पण और खेल भावना का उत्कृष्ट परिचय दिया। भारतीय दल ने चौथे दौर में थाईलैंड 'बी' दल को 3–0 से पराजित किया। इसके बाद अर्ध–फाइनल मुकाबले में फिनलैंड के दल को तीन–एक से हराकर फाइनल मुकाबले में प्रवेश किया। फाइनल मुकाबले में भारतीय दल को थाईलैंड 'ए' दल के विरुद्ध तीन–शून्य से पराजय का सामना करना पड़ा। 40 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में भारत की ओर से विक्रम, विकास, मनमीत और हरजिंदर ने दल का प्रतिनिधित्व किया। इस उपलब्धि पर विकास महाजन ने कहा कि देश के लिए खेलकर भारत का नाम रोशन करना उनके लिए गर्व का विषय है। उनका यह प्रदर्शन युवाओं और खिलाडियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इस गौरवपूर्ण उपलब्धि की खुशी और राष्ट्र गौरव की भावना के साथ आज जिमखाना क्लब परिसर में गणतंत्र दिवस को पूरे जोश, उत्साह और देशभक्ति के वातावरण में भव्य रूप से मनाया गया। इस दौरान विकास व उनकी टीम को सम्मानित किया गया। आज का कार्यक्रम प्रशिक्षक अरुण, प्रशिक्षक रजत, प्रशिक्षक नेहा, प्रशिक्षक नंदनन और प्रशिक्षक कीर्ति द्वारा सामूहिक रूप से आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम खेल, टीम भावना और राष्ट्रप्रेम का सुंदर उदाहरण बना। सभी ने मिलकर इस अवसर को यादगार बनाया और विकास महाजन के उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

भविष्य निर्माण के लिए अतीत के सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ाव जरूरी

देश में स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग पर जोर देने और भारतीय शिक्षा के प्रसार के लिए दयानंद एंग्लो–वैदिक विद्यालयों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लाला लाजपत रायका जन्म पंजाब के मोगा जिले केधुडीके गांव में 28 जनवरी 1865 को एक अग्रवाल जैन परिवार में पिता फारसी व उर्दू के विद्वान मुंशी कृष्ण आजाद व माता धर्म परायनी गुलाब देवी के घर में हुआ था।लाला लाजपत राय ने हरियाणा के रोहतक और हिसार के सरकारी विद्यालयों में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद 1880 में लाहौर के राजकीय कॉलेजमें कानून की पढ़ाई करने के लिए प्रवेश लिया।1886 में उन्होंने हिसार में वकालत शुरू की। बाद में वे लाहौर चले गए और पंजाब उच्च न्यायालय में वकालत करने लगे। लाला लाजपत राय न केवल एक शिक्षित वकील थे, बल्कि उन्होंने भारतीय शिक्षा प्रणाली को सुधारने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था।विशेष रूप से हरियाणा के हिसार और रोहतक में उनकी वकालत और आर्य समाज के माध्यम से किए गए सुधारात्मक कार्य उनके व्यक्तित्व के बहुआयामी होने के प्रमाण हैं।उन्होंने 1894 में स्वदेशी की भावना के साथ पंजाब नेशनल बैंक की नींव रखने में मदद की, जो आज भी भारत के प्रमुख बैंकों में से एक है। वे 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी चुने गए थे।1921 में उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ द पीपुल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना की, जिसका उद्देश्य अछूतोद्धार और सामाजिक सेवा के लिए युवाओं को प्रशिक्षित करना था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में लाल, बाल, पाल नाम से प्रसिद्ध त्रिमूर्ति के सबसे प्रमुख नेताओं में से एक और पंजाब केसरी अर्थात पंजाब का शेर के नाम से लोकप्रिय लाला लाजपत राय ने बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल के साथ मिलकर कांग्रेस के भीतर गरम दल का नेतृत्व किया। उन्होंने पूर्ण स्वराज (स्वतंत्रता) की वकालत की और ब्रिटिश शासन के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया।1905 के बंगाल विभाजन के विरोध में उन्होंने स्वदेशी आंदोलन को पंजाब और शेष भारत में मजबूती से फैलाया। उन्होंने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और भारतीय उत्पादों के उपयोग पर जोर दिया।शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।लाला हंसराज के साथ मिलकर दयानंद एंग्लो वैदिकसंस्थानों की स्थापना करना उनके दूरदर्शी होने का प्रतीक था, ताकि भारतीय युवाओं को आधुनिक शिक्षा के साथ–साथ अपनी संस्कृति का भी ज्ञान मिले। एक प्रखर लेखक के रूप में लाला लाजपत राय ने अनहैप्पी इंडिया, इंग्लैंड्स डेट टू इंडिया,द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ आदि प्रसिद्ध पुस्तकें लिखीं और यंग इंडिया, द पंजाबी आदि पत्रिकाओं का प्रकाशन भी किया।आज के संदर्भ में, 2026 में भी उनकी शिक्षाएं और राष्ट्रवाद के प्रति उनका समर्पण करोड़ों भारतीयों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। ऐतिहासिक विवरणियों के अनुसार 30 अक्टूबर 1928 को लाला लाजपत राय लाहौर में साइमन कमीशन के खिलाफ एक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे, जहां उन्होंने प्रसिद्ध नारा दिया– साइमन गो बैक। विरोध को दबाने के लिए ब्रिटिश पुलिस अधीक्षक जेम्स ए. स्कॉट ने लाठीचार्ज का आदेश दिया। इस दौरान लाला जी के सीने और सिर पर गंभीर चोटें आईं। इन गंभीर चोटों के कारण उनका स्वास्थ्य बिगड़ता गया और 17 नवम्बर 1928 को लाहौर (अब पाकिस्तान) में उनका निधन हो गया हो। उनकी मृत्यु का मुख्य कारण ब्रिटिश पुलिस द्वारा किया गया हिंसक लाठीचार्ज था। 30 अक्टूबर 1928 कोब्रिटिश पुलिस की पिटाई से घायल होने के बाद उन्होंने ऐतिहासिक शब्द कहे थे– मेरे शरीर पर पड़ी एक–एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। उनका यह अंतिम सार्वजनिक उक्ति आज भी राष्ट्रवाद का सबसे शक्तिशाली प्रतीक माना जाता है। 30 अक्टूबर 1928 की वह घटना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक निर्णायक मोड़ साबित हुई थी। 17 नवम्बर 1928 को लालाजी की मृत्यु ने पूरे देश को झकझोर दिया था।इस घटना ने भारत की पूर्ण स्वराज की मांग को एक नई दिशा और ऊर्जा प्रदान की थी। उनके बलिदान ने भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन की आग में घी का काम किया था।उनके बलिदान का बदला लेने के लिए ही भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने मूल रूप से जे.ए. स्कॉट को मारने की योजना बनाई थी, क्योंकि उसी ने लाठीचार्ज का आदेश दिया था। हालांकि, पहचान की चूक के कारण सहायक पुलिस अधीक्षक जॉन पी. सॉन्डर्स मारा गया। इसके बाद क्रांतिकारियों ने पर्चे बांटे थे जिन पर लिखा था– लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला ले लिया गया है। इसी लाहौर केसके कारण अंततः 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई। इस तरह लालाजी के बलिदान ने न केवल युवाओं को प्रेरित किया, बल्कि ब्रिटिश शासन के अंत की शुरुआत भी कर दी थी। लाला लाजपत राय न केवल एक स्वतंत्रता सेनानी थे, बल्कि एक दूरदर्शी समाज सुधारक और उद्यमी भी थे।उनके द्वारा 1894 में स्थापित पंजाब नेशनल बैंक, लक्ष्मी बीमा कंपनी, आदि स्वदेशी वित्तीय संस्थान तथा पंजाब और उत्तर भारत में स्थापित डीएवी विद्यालयों और कॉलेज आदि संस्थाएं संस्थाएं आज भी भारत की आर्थिक और शैक्षिक नींव को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं, जो लाला लाजपत राय की दूरदर्शिता को सिद्ध करती हैं।लाला लाजपत राय के साहित्यिक और भाषाई योगदान को भी भुलाया नहीं जा सकता। वे केवल एक राजनेता नहीं, बल्कि एक प्रखर विद्वान और हिन्दी के प्रबल समर्थक भी थे।उन्होंने शिवाजी और श्रीकृष्ण के साथ–साथ मैजिनी और गैरीबॉल्डी जैसे अंतरराष्ट्रीय क्रांतिकारियों की जीवनियां इसलिए लिखीं ताकि भारतीय युवा उनसे देशभक्ति की प्रेरणा ले सकें। उनका मानना था कि भाषा राष्ट्र की एकता का आधार होती है। उन्होंने पंजाब में उर्दू के प्रभुत्व के बीच हिन्दी को पहचान दिलाने के लिए कड़ा संघर्ष किया।उन्होंने हिन्दी को आधिकारिक भाषा के रूप में स्थापित करने हेतु व्यापक जन–समर्थन जुटाया था। हस्ताक्षर अभियान भी चलाया था।उनकी प्रसिद्ध पुस्तक अनहैप्पी इंडियाब्रिटिश शासन के दुष्प्रचार का करारा जवाब थी। इसका हिन्दी अनुवाद दुखी भारतनाम से हुआ।वर्ष 2026 में भी, जब भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीतिके माध्यम से भारतीय भाषाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है,लालाजी के हिन्दी सेवा के प्रयास अत्यंत प्रासंगिक प्रतीत होते हैं।लाला लाजपत राय के कुछ अत्यंत प्रेरणादायक और दूरदर्शी अनमोल वचन आज भी प्रासंगिक हैं। ये विचार आज 2026 में भी उतने ही प्रासंगिक हैं, जितने उनके जीवनकाल में थे।लाला लाजपत राय कायह कथन आज भी हमें शीघ्र कार्रवाई की आवश्यकता और सतत प्रगति की सोच को उजागर करने के लिए प्रेरित करता है, जिसमें उन्होंने कहा था –अतीत को देखते रहना व्यर्थ है, जब तक उस अतीत पर गर्व करने योग्य भविष्य के निर्माण के लिए कार्य न किया जाए। उल्लेखनीय है कि अतीत पर गर्व करने योग्य भविष्य के निर्माण के लिए कार्य करना, न केवल एक विचार है, बल्कि राष्ट्र के उत्थान का एक ठोस मार्ग है।

Printed, Published,Edited, & Owned by Prakash Kumar Dhal, Printed at Promodini Publication, Main road , Chhend colony , Rourkela-15 & Published at ECR-73, Chhend Colony, Rourkela-15, Editor : Prakash kumar Dhal, Email:kalingasamachar@gmail.com , Mob: 9439951525, Ph. 0661-2646999

ओडिशा समाचार

कलिंग समाचार | राउरकेला, रविवार 08 मार्च 2026 | पृष्ठ-6

लकड़ी तस्करी पर शिकंजा, लाखों की जब्ती

गंजम ०७/०३ (संवाददाता): वन विभाग ने गंजम जिले के भंजनगर में दक्षिण घुमुसर वन प्रभाग के बडागड़ा वन रेंज के तहत गंगापुर गांव के पास अवैध लकड़ी तस्करी की कोशिश को नाकाम कर दिया और 3 लाख रुपये से ज़्यादा की लकड़ी और गाड़ी ज़ब्त की।

एक सूचना के आधार पर, वन अधिकारियों ने कीमती लकड़ी से लदी एक पिकअप वैन को ज़ब्त कर लिया, जिससे उसकी अवैध ढुलाई रोक दी गई। अधिकारियों के अनुसार, जानकारी मिली थी कि एक पिकअप वैन का इस्तेमाल महंगी लकड़ी की तस्करी के लिए किया जा रहा है। इसके बाद, बडागड़ा रेंज के वन अधिकारी ने एक विशेष प्रवर्तन टीम के साथ मिलकर एक ऑपरेशन शुरू किया और संदिग्ध वाहन का पीछा करना शुरू कर दिया। वन विभाग की गाड़ी को देखते ही ड्राइवर पिकअप वैन छोड़कर मौके से फरार हो गया। वन टीम ने गंगापुर गांव के पास लकड़ी से लदी गाड़ी को सफलतापूर्वक रोक लिया और ज़ब्त कर लिया।

ज़ब्त किए गए माल में सागौन और गंभारी की लकड़ी शामिल थी, जिन्हें कीमती वन उत्पाद माना जाता है। अधिकारियों ने पुष्टि की कि ऑपरेशन के दौरान कुल 46 ष्ढ्ढह्ल लकड़ी बरामद की गई।

बडागड़ा के रेंज वन अधिकारी अंजन कुमार नायक ने कहा, हमें मिली जानकारी के आधार पर, हम पिछले चार दिनों से संदिग्धों पर नज़र रख रहे थे। कल रात, हमने उन्हें सफलतापूर्वक रोक लिया, और पुलिस की मदद से, हम गाड़ी का पता लगाकर उसे ज़ब्त करने में कामयाब रहे। ज़ब्त की गई लकड़ी की कीमत 70,000 रुपये से ज़्यादा होने का अनुमान है, जबकि गाड़ी की कीमत 2 लाख रुपये से ज़्यादा है। कुल मिलाकर, ज़ब्त की गई संपज़ि की कीमत 3 लाख रुपये से ज़्यादा है।

ज़ब्त की गई पिकअप वैन और लकड़ी की अनुमानित कीमत लगभग 3 लाख रुपये है। बडागड़ा रेंज के वन अधिकारी ने बताया कि तस्करी नेटवर्क में शामिल लोगों की पहचान के लिए आगे की जांच जारी है।

यह सफल ऑपरेशन अवैध लकड़ी व्यापार पर अंकुश लगाने और वन संसाधनों की रक्षा के लिए वन विभाग के लगातार प्रयासों को उजागर करता है। अधिकारियों ने दोहराया है कि वन संबंधी अपराधों में शामिल लोगों के खिलाफ सज़्त कार्रवाई की जाएगी, जिससे क्षेत्र में सक्रिय लकड़ी तस्करों को एक स्पष्ट चेतावनी दी गई है।

सरकार ने 18 जिलों में नगर निकाय चुनावों की प्रक्रिया शुरू की

भुवनेश्वर ०७/०३ (संवाददाता): नई बनी नोटिफाइड एरिया काउंसिल (ह्रष्टह्य), नगर पालिकाओं और नगर निगमों के चुनावों की प्रक्रिया शुरू करते हुए, ओडिशा सरकार ने इस संबंध में 18 जिलों के जिला कलेज़्टरों को पत्र लिखा है। एक पत्र में, आवास और शहरी विकास विभाग ने कलेज़्टरों को मार्च तक वार्डों के परिसीमन और सीटों के आरक्षण की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है। शेड्यूल के अनुसार, नगर पालिका क्षेत्रों के परिसीमन और सीटों के आरक्षण से संबंधित प्रस्ताव और आपज़ियां 12 फरवरी से 21 फरवरी तक आमंत्रित की जाएंगी। परिसीमन और सीटों के आरक्षण पर नोटिफिकेशन 26 फरवरी को जारी किया जाएगा। इसके बाद, 26 फरवरी से 13 मार्च तक आपज़ियां और अपील स्वीकार की जाएंगी।

स्टील मेल्टिंग शॉप-1 में इन-हाउस विकसित नए 'पाम ट्री उद्यान' का उद्घाटन

राउरकेला ०७/०३ (संवाददाता):राउरकेला इस्पात संयंत्र (आरएसपे) के स्टील मेल्टिंग शॉप-1 (एसएमएस-1) समूह की एक नई हरित पहल के अंतर्गत इन-हाउस विकसित 'पाम ट्री उद्यान' का उद्घाटन 29 जनवरी 2026 को कार्यपालक निदेशक (संकार्य), श्री बिस्वरंजन पलई द्वारा किया गया। इस अवसर पर मुज़्य महाप्रबंधक (एसएमएस-1), श्री बी सुनील कार्था, कई अन्य मुज़्य महाप्रबंधकगण, वरिष्ठ अधिकारी तथा बड़ी संज़्या में कर्मचारी उपस्थित थे।

इस अवसर पर संबोधित करते हुए श्री पलई ने परिचालन क्षेत्र के भीतर हरियाली को बढ़ावा देने के लिए एसएमएस-1टीम के सक्रिय प्रयासों की सराहना की और ऐसे प्रयासों के महत्व पर जोर दिया, जो एक स्वस्थ एवं प्रेरणादायी कार्य वातावरण के निर्माण में सहायक होते हैं।

खूबसूरती से विकसित किया गया यह बगीचा एक मनमोहक हरा-भरा स्थान प्रदान करता है और पर्यावरण स्थिरता और कार्यस्थल के सौंदर्यीकरण के प्रति संयंत्र की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

उल्लेखनीय है कि यह उद्यान उस ज़मीन के एक टुकड़े पर विकसित किया गया है, जो पूर्व में अनुपयोगी एवं जर्जर अवस्था में पड़ा हुआ था तथा झाड़ियों और खरपतवारों से घिरा हुआ था। एसएमएस-1 कर्मीसमूह के समन्वित इन-हाउस प्रयासों से इस क्षेत्र को एक सुव्यवस्थित हरित क्षेत्र में परिवर्तित किया गया है, जिससे शॉप परिसर की सौंदर्यता और पर्यावरणीय गुणवज़ा दोनों में सुधार हुआ है।

बीजेडी ने फॉर्म 17सी पर ईसीआई की चूक और वोटों में भारी उछाल को लेकर चिंता जताई

भुवनेश्वर ०७/०३ (संवाददाता): ओडिशा में हुए दोहरे चुनावों के उन्नीस महीने बाद, बीजू जनता दल (बीजेडी) ने भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) द्वारा फॉर्म 17सी और वोटों में अचानक हुई बढ़ोतरी से संबंधित खामियों का मुद्दा उठाया। बीजेडी ने पूर्ण पारदर्शिता की अपनी मांग को दोहराते हुए कहा कि भारत निर्वाचन आयोग ने 2024 के ओडिशा चुनावों से संबंधित प्रमुख चिंताओं पर अभी तक स्पष्ट जवाब नहीं दिए हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, पार्टी के वरिष्ठ नेता संतृप्त मिश्रा और लेखाश्री सामंता सिंघर ने इस बात पर जोर दिया कि नवीन पटनायक की ओर से उठाई गई मांगें लोकतंत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से हैं, न कि राजनीति को।फॉर्म 17सी अभी भी लापता है- 19 महीने बीत जाने के बाद भी बूथवार मतदान के रिकॉर्ड प्रकाशित नहीं हुए हैं।

मतदान में विसंगतियां- डाले गए वोटों (फॉर्म 17सी) और गिने गए वोटों (फॉर्म 20) के बीच बड़ा अंतर है, कुछ बूथों पर 600 से अधिक अतिरिक्त वोट दिखाए गए हैं। शाम 5 बजे के बाद मतदान में अचानक उछाल- सभी निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान के आंकड़ों में 7त्न से 30त्न की वृद्धि - जो पहले के चुनावों में नहीं देखी गई थी - अभी भी अस्पष्ट है।

खोए हुए वोट- ईवीएम/प्रक्रियात्मक त्रुटियों के कारण मतपत्र अमान्य घोषित किए गए, और इसके लिए कोई जवाबदेही तय नहीं की गई।पारदर्शिता की मांग- बीजेडी ने ईवीएम ऑडिट में पार्टी की भागीदारी और मजबूत सुरक्षा उपायों की मांग की है।

पार्टी ने चुनाव आयोग से जनता का विश्वास बहाल करने और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए शीघ्र और स्पष्ट स्पष्टीकरण देने का आग्रह किया।

बार के अंदर हंगामा करने के आरोप में चार लोग गिरफ्तार

भुवनेश्वर ०७/०३ (संवाददाता): मंचेश्वर पुलिस ने शहर के पलासुनी इलाके के एक बार में हिंसक हंगामे और जबरन वसूली की कोशिश के सिलसिले में चार लोगों को गिरज़्तार किया है। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। यह घटना 1 जनवरी, 2026 की रात को मंचेश्वर पुलिस की सीमा के तहत रसूलगढ़ में एक बार के पास हुई। पुलिस ने जिन आरोपियों की पहचान की है, वे हैं पूर्ण चंद्र शियाल (25), देबी प्रसाद बारिक (21), प्रियब्रत खटुआ (22) और आशुतोष मोहंती। पुलिस के मुताबिक, चारों आरोपी, दो अन्य लोगों के साथ, नशे की हालत में रसूलगढ़ के पास एक बार में घुसे और बार स्टाफ से पैसे मांगे।

ज़्लैकमेल और उत्पीड़न से परेशान होकर छात्रा ने आत्महत्या कर ली

कोरापुट ०७/०३ (संवाददाता): ओडिशा के कोरापुट जिले के दासमनपुर ज़्लॉक के गाडियागुड़ा इलाके में एक छात्रा ने कथित तौर पर लगातार मानसिक उत्पीड़न और ज़्लैकमेल का सामना करने के बाद आत्महत्या कर ली। इस घटना से पूरे इलाके में सदमे की लहर दौड़ गई है और युवा छात्रों के उत्पीड़न और सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा हो गई हैं। शुरुआती जानकारी के अनुसार, छात्रा को कथित तौर पर लगातार मानसिक यातना, धमकियों और ज़्लैकमेल का शिकार बनाया जा रहा था, जिससे वह कथित तौर पर गंभीर तनाव में आ गई थी। परिवार के सदस्यों और स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि उत्पीड़न कुछ समय से चल रहा था, जिससे पीड़िता पर बहुत ज़्यादा मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ रहा था।

परिवार द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, छात्रा पर बार-बार उसकी तस्वीरें वायरल करने की धमकी दी जा रही थी, जिससे वह गंभीर मनोवैज्ञानिक दबाव में थी। परिवार ने आरोप लगाया है कि बदमाश उसे शारीरिक संबंध बनाने के लिए भी मजबूर कर रहे थे, जिससे उसे बहुत ज़्यादा मानसिक परेशानी हुई। यह घटना तब सामने आई जब लड़की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाई गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। मौत के सही कारण का पता लगाने के लिए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। इस घटना के बाद ज़्लैकमेल और उत्पीड़न के आरोप सामने आए हैं, जिसके बाद दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि वे उत्पीड़न के आरोपों सहित सभी संभावित पहलुओं की जांच कर रहे हैं और मामले से जुड़े लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि विस्तृत जांच चल रही है और आश्वासन दिया कि जांच के नतीजों के आधार पर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

इस घटना से इलाके में गुस्सा फैल गया है, निवासी न्याय और छात्रों के उत्पीड़न को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। आगे की जांच जारी है।

पीने के पानी की कमी को लेकर ग्रामीणों ने सड़कें जाम कीं

बालासोर ०७/०३ (संवाददाता): बैंचा और नारनपुर के बीच वाहनों की आवाजाही लगभग तीन घंटे तक ठप रही, ज़्योंकि नीलगिरी ज़्लॉक के मटियाली पंचायत के आदिआसाही, डंबुरिया और रामसिंह साही गांवों के गुस्साए ग्रामीणों ने इलाके में पीने के पानी के संकट का तुरंत समाधान करने की मांग को लेकर आदिअखुंटा चौक पर सड़क जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने सुबह 10 बजे से सड़क पर बर्तन, बाल्टी और कंटेनर रखकर जाम लगा दिया। उन्होंने कहा कि मटियाली से सिर्फ एक किलोमीटर दूर एक मेगा जल आपूर्ति परियोजना स्थापित की गई है। हालांकि, इन गांवों में पानी की आपूर्ति अनियमित बनी हुई है।ग्रामीणों ने कहा, हम चाहते हैं कि प्रशासन हमारे इलाके में पीने के पानी के संकट को हल करने के लिए स्थायी उपाय करे।

जूनियर इंजीनियरों के साथ स्थानीय पुलिस विरोध स्थल पर पहुंची और ग्रामीणों को जल्द से जल्द इस मुद्दे को हल करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद सड़क जाम हटा लिया गया।

आईआईटी भुवनेश्वर की स्टडी में विश्वसनीयता, ऑपरेशनल दक्षता, तकनीकी प्रगति और ग्राहक-केंद्रितता में सुधारों को मान्यता दी गई

भुवनेश्वर ०७/०३ (संवाददाता): इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेज़्नोलॉजी (आईआईटी) भुवनेश्वर ने टाटा पावर और ओडिशा सरकार के जॉइंट वेंचर TP सेंट्रल ओडिशा डिस्ट्रीज़्यूशन लिमिटेड (TPCODL) के पावर डिस्ट्रीज़्यूशन परफॉर्मेंस पर एक स्टडी जारी की है। इसमें जांच की गई है कि डिस्ट्रीज़्यूशन सेज़्टर में सुधारों के बाद पांच साल की अवधि में नेटवर्क की विश्वसनीयता, ऑपरेशनल दक्षता, तकनीकी हस्तक्षेप और ग्राहक सेवा डिलीवरी में कैसे बदलाव आया है। यह स्टडी लगातार पूंजी निवेश, नेटवर्क आधुनिकीकरण और डिस्ट्रीज़्यूशन नेटवर्क में डिजिटल टेज़्नोलॉजी को अपनाने के परिणामों का मूल्यांकन करती है।

यह स्टडी आईआईटी भुवनेश्वर के इलेज़्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग, स्कूल ऑफ इलेज़्ट्रिकल एंड कंप्यूटर साइंसेज के प्रो. चंद्रशेखर भेडे (प्रोफेसर), डॉ. चंद्रशेखर पेरुमल्ला (एसोसिएट प्रोफेसर) और डॉ. अभिनीत प्रकाश (असिस्टेंट प्रोफेसर) ने तैयार की है। यह TPCODL के परफॉर्मेंस का आकलन करती है, जो सेंट्रल ओडिशा में 29,354 वर्ग किमी में 1.36 करोड़ लोगों को सेवा प्रदान करता है। यह विश्लेषण फील्ड निरीक्षण, सिस्टम डेटा के सत्यापन और शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में ऑपरेशनल और उपभोक्ता सेवा प्रथाओं की समीक्षा पर आधारित है।

स्टडी का एक मुख्य निष्कर्ष आउटेज की अवधि में महत्वपूर्ण कमी है, जो समीक्षा अवधि में सिस्टम एवरेज इंटरप्शन ड्यूरेशन इंडेज़्स (SAIDI) में लगभग 50 प्रतिशत के सुधार में परिलक्षित होता है। यह सुधार एक अधिक स्थिर और लचीले डिस्ट्रीज़्यूशन नेटवर्क को इंगित करता है, जिसे बेहतर फॉल्ट डिटेज़्शन, तेजी से फॉल्ट आइसोलेशन और बेहतर बहाली प्रक्रियाओं द्वारा समर्थित किया गया है, जिसने ट्रांसफार्मर ट्रिपिंग दरों और ट्रांसफार्मर विफलता दरों में कमी में भी योगदान दिया है।

स्टडी में ऑपरेशनल दक्षता में भी उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई है, जिसमें एग्रीगेट टेज़्निकल एंड कमर्शियल (AT&C) नुकसान सुधार अवधि की शुरुआत में लगभग 30 प्रतिशत से घटकर FY 25 में 18.94 प्रतिशत हो गया है। यह सुधार बेहतर ऑपरेशनल नियंत्रण, बेहतर बिलिंग प्रक्रियाओं और बढ़ी हुई नेटवर्क दक्षता के कारण हुआ है, जिसे 33 kv फीडर में 44 प्रतिशत की वृद्धि, 11 kv फीडर में 42 प्रतिशत की वृद्धि और 250 सबस्टेशनों को एक केंद्रीकृत नियंत्रण केंद्र में एकीकृत करने से समर्थन मिला है। पांच साल की अवधि में, 1,500 करोड़ से अधिक का पूंजी निवेश सबस्टेशनों को मजबूत करने, ऑटोमेशन कवरेज का विस्तार करने, डिजिटल निगरानी प्लेटफॉर्म तैनात करने और समग्र नेटवर्क लचीलेपन को बढ़ाने की दिशा में किया गया है। स्टडी में बताया गया है कि साइज़्लोन से निपटने वाले डिस्ट्रीज़्यूशन नेटवर्क को डेवलप करने के लिए किए गए खास प्रयासों, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना और रिडंडेंसी प्लानिंग शामिल है, के कारण साइज़्लोन से प्रभावित इलाकों में 24 से 48 घंटों के भीतर बिजली बहाल हो गई है, जो बेहतर तैयारी और रिस्पॉन्स क्षमता को दिखाता है।

कस्टमर सेंट्रिसिटी और सर्विस डिलीवरी मैकेनिज़्म के विकास पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया गया है। स्टडी में कस्टमर सर्विस के तरीकों के विस्तार पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें 24×7 कॉल सेंटर और 20 कस्टमर केयर सेंटर, कई डिजिटल पेमेंट ऑप्शन की उपलज़्धता और शिकायतों, सर्विस रिक्वेस्ट और जानकारी फैलाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का ज़्यादा इस्तेमाल शामिल है। बिलिंग की सटीकता में सुधार, प्रोविजनल बिलिंग में काफी कमी और कस्टमर के साथ एज़्टिव कज़्युनिकेशन ने पारदर्शिता, कस्टमर के भरोसे और सर्विस की क्वालिटी को बेहतर बनाने में योगदान दिया है।

डिसेंट्रलाइज्ड फॉल्ट रिस्पॉन्स को सर्विस में सुधार का एक महत्वपूर्ण जरिया माना गया है, खासकर भौगोलिक रूप से फैले हुए इलाकों में। शहरी इलाकों में 131 ज़्यूज कॉल सेंटर और ग्रामीण इलाकों में 811 कॉल सेंटर का नेटवर्क पूरे लाइसेंस एरिया में पहले लेवल के फॉल्ट रिस्पॉन्स को सपोर्ट करता है, जबकि सेंट्रलाइज्ड मॉनिटरिंग और शिकायत निवारण सिस्टम के साथ डिजिटल रूप से इंटीग्रेटेड रहता है। इन सेंटरों के ग्रामीण इलाकों में विस्तार से ग्रामीण जगहों पर ऐतिहासिक रूप से लंबे रिस्पॉन्स टाइम को कम करने में मदद मिली है, जिससे FY25 में कस्टमर सैटिस्फैज़्शन स्कोर 96 प्रतिशत तक पहुंच गया है।

यह स्टडी TPCODL के परफॉर्मेंस को व्यापक राष्ट्रीय पावर सेज़्टर सुधार फ्रेमवर्क के तहत रखती है, और यह नोट करती है कि यह दक्षता, कस्टमर सेंट्रिकिटी और विज़ीय स्थिरता पर राष्ट्रीय बिजली नीति के उद्देश्यों के साथ-साथ प्रस्तावित बिजली अधिनियम संशोधनों के इरादे के अनुरूप है, खासकर जवाबदेही और डिस्ट्रीज़्यूशन दक्षता के संबंध में। यह तालमेल TPCODL की बिजली मंत्रालय द्वारा 14वीं वार्षिक इंटीग्रेटेड रेटिंग और रैंकिंग में A+ रेटिंग में झलकता है, जो ऑपरेशनल, विज़ीय और कस्टमर-केंद्रित परफॉर्मेंस में उत्कृष्टता के लिए लगातार तीन वर्षों तक टॉप-टियर मान्यता को दर्शाता है।